हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 213 बेमेतरा, शनिवार 28 मार्च 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षेप समाचार

तीसरी बार बम धमकी से दहशत, जिला न्यायालय की सुरक्षा कड़ी

बिलासपुर। बिलासपुर स्थित जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। न्यायालय प्रशासन को ई-मेल के जरिए मिली इस धमकी में कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई है। यह लगातार तीसरी बार है जब इस तरह की धमकी सामने आई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर न्यायालय परिसर की सघन जांच की। इस दौरान कोर्ट रूम, गलियारों, प्रवेश द्वारों और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से तलाशी ली गई। एहतियात के तौर पर न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि नियमित सुरक्षा जांच के अलावा इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

इजरायल ने मध्य तेहरान पर बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार हमले किए : आईडीएफ

मास्को। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि उसने मध्य तेहरान पर बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार हमले किए। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा, कुछ देर पहले आईडीएफ ने तेहरान के केंद्र में ईरानी आतंकी शासन अवसंरचना को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए। इसी बीच, प्रेस टीवी ने खबर दिया है कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 83वीं लहर शुरू कर दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अभियान के दौरान, ईरानी सशस्त्र बलों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जर्मनी, भारत, स्पेन और पाकिस्तान के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 900 अंक लुढ़का

मुंबई। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट रही। बीएसई का सेंसेक्स 389.66 अंक टूटकर 74,883.79 अंक पर खुला। बिकवाली के दबाव में सूचकांक और टूटता हुआ खबर लिखे जाते समय 903.84 अंक (1.20 प्रतिशत) नीचे 74,369.61 अंक पर था।

पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती

नयी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। सरकार के इस निर्णय से तेल विपणन कंपनियों पर दबाव कम होगा और उन्हें फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने होंगे। वित्त मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में बताया कि पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर घरेलू इस्तेमाल वाले पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गयी है। इससे ग्राहकों को मूल्य वृद्धि से सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने

बताया कि इसकी जानकारी संसद को भी दे दी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण तेल विपणन कंपनियों पर दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम बढ़ाने का दबाव था। उत्पाद शुल्क में कटौती से उन्हें राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्च का ब्रेंट क्रूड वायदा फिलहाल 0.5 प्रतिशत गिरकर करीब 107.5 डॉलर प्रति बैरल पर है। पश्चिम एशिया संकट के बाद से इसकी कीमत करीब 50 फीसदी बढ़ चुकी है। यह कटौती सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश को किये जाने वाले निर्यात पर भी लागू होगी। इसके अलावा, सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये और विमान ईंधन के निर्यात पर 29.5 प्रति लीटर का शुल्क लगाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश में डीजल और विमान ईंधन की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। पेट्रोल डीजल के निर्यात पर विशेष उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्यातित पेट्रोल पर विशेष उत्पाद शुल्क शून्य है जबकि डीजल पर 18.5 रुपये प्रति लीटर है।

मुख्यमंत्री ने कहा—140 करोड़ नागरिकों को सीधी राहत देने वाला ऐतिहासिक निर्णय

पेट्रोल 10 रूपए सस्ता, केंद्र सरकार के फैसले का मुख्यमंत्री साय ने किया स्वागत

रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करने और पेट्रोल पर 10 प्रति लीटर की कटौती करते हुए एक्साइज ड्यूटी को मात्र 3 प्रति लीटर करने के निर्णय का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के 140 करोड़ नागरिकों को सीधी राहत पहुंचाने वाला ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस निर्णय से देश के प्रत्येक परिवार, किसान, श्रमिक और मध्यमवर्ग को व्यापक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में भी केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न बढ़ने देना एक बड़ी संवेदनशील पहल है, जो आमजन के जीवन

को सीधे प्रभावित करेगी। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले रही है। यह फैसला प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और देशवासियों के प्रति समर्पण का सशक्त उदाहरण है।

हरदीप पुरी ने देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहां दुनिया ईंधन की कमी से गुजर रही है, वहीं भारत में ईंधन की प्रचुर उपलब्धता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में पुरी ने कहा कि जहाँ दुनिया के अन्य देश ईंधन संरक्षण के लिए ऑड-ईवन, सप्ताह में चार दिन काम और स्कूलों-कार्यालयों को बंद करने जैसे कड़े कदम उठा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता का एक बेमिसाल उदाहरण बना हुआ है। पुरी ने घोषणा की कि वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने राज्यों के वाणिज्यिक

एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20 प्रतिशत आवंटन स्टील, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम-गहन उद्योगों को दिया जाएगा। उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ 'पाइप्ड गैस' एक विकल्प नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 30-50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में 30 प्रतिशत, यूरोप में 20 प्रतिशत और अफ्रीकी देशों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल उत्पाद शुल्क कटौती को बताया 'जनता से वसूली का खेल'

नयी दिल्ली। राज्यसभा में उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर शुक्र को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईंधन में उत्पाद शुल्क कटौती जनता से वसूली का खेल है।

तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार पहले जनता से भारी वसूलती है और बाद में मामूली राहत देकर उसे उपकार के रूप में पेश करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.48 रूपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रूपए प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर क्रमश: लगभग 32.98 रूपए और 31.83 रुपए प्रति लीटर हो गई है। उन्होंने इसे जनता पर बढ़ता आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि सरकार ने इन करों के जरिए लाखों करोड़ रुपये वसूले हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अब सरकार खुद को राहत देने वाली बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि आम लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लगता है जो फाइल है, उसका कुछ असर अब दिमाग पर भी दिखने लगा है।

गौरतलब है कि सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को 10 रुपए प्रति लीटर घटा दिया है।

इससे पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर तीन रुपए प्रति लीटर हो गई है।

बालेंद्र शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री नयुक्त

काठमांडू। नेपाल में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के संसदीय दल के नेता बालेंद्र शाह को नेपाल का 47वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय से शुक्रवार को उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा के साथ ही नए मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। शाह को प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में संविधान की धारा 76 (1) के तहत यह पद सौंपा गया है। वह काठमांडू महानगर पालिका के मेयर पद से इस्तीफा देकर राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर उतरे और लोगों ने उन पर भरोसा जताया। हाल ही में संपन्न हुए

चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद श्री शाह पहली बार संसद सदस्य के रूप में प्रवेश करते ही देश के कार्यकारी प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। पेशे से इंजीनियर और लोकप्रिय सांस्कृतिक पहचान रखने वाले शाह के नेतृत्व में नेपाल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत मानी जा रही है।

नेपाल के नए प्रधानमंत्री को पीएम मोदी ने भेजा बधाई संदेश, कहा- संबंधों को नई ऊंचाईयों पर लेकर जाएंगे

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन को शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए भारत-नेपाल संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं। रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने लगभग लगभग छह महीने बाद हुआ है। ओली सरकार को एक युवा पीढ़ी के विरोध प्रदर्शन में हटा दिया गया था।

पीएम ने क्या कहा ?

मोदी ने एक्स पर एक संदेश में कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बालेंद्र शाह को हार्दिक बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाल की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए भरोसे को दर्शाती है।

सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार, एक-दो दिन में अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उनके डॉक्टरों ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें एक-दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। 79 वर्षीय नेता को 25 मार्च रात करीब 10:22 बजे बुखार आने के बाद सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अध्यक्ष अजय स्वरूप के अनुसार, सोनिया गांधी अब काफी बेहतर हैं और सहज महसूस कर रही हैं। वे चल-फिर रही हैं और उन्होंने नाश्ता भी किया है। उनकी प्रगति सुचारू है और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिलने की उम्मीद है। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सिस्टेमिक इन्फेक्शन का इलाज दिया जा रहा है। वह एंटीबायोटिक दवाओं पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं। उनकी हालत स्थिर है और गंभीर नहीं है, हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ समय निगरानी में रहेंगी।

बे मौसम हुई बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होने के संकेत हैं, जिससे गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है।

फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के कारण मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। दिन और रात के तापमान में अंतर साफ तौर पर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तरी ओडिशा से सटे दक्षिण गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बने ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण का असर अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहा है। यही सिस्टम प्रदेश में मौसम बदलाव का प्रमुख कारण बन रहा है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है।

ट्रम्प ने ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमले को 10 दिनों के लिए किया स्थगित

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। ट्रम्प ने कहा कि वे इस प्रक्रिया को छह अप्रैल को पूर्वी समयानुसार रात आठ बजे तक के लिए स्थगित कर रहे हैं। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, ईरानी सरकार के अनुरोध पर, मैं ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की अवधि को 10 दिनों के लिए सोमवार, छह अप्रैल को रात आठ बजे (पूर्वी समय) तक रोक रहा हूं।

उन्होंने दोहराया कि बातचीत जारी है और फर्जी मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद, यह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हालांकि ईरान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत चल रही है।

तेहरान, इस्फहान सहित कई ईरानी शहरों में इजरायल के मिसाइल हमले

तेहरान। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के 28वें दिन तेहरान, इस्फहान और आसपास के क्षेत्रों में कई हवाई हमले किए गए, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गयीं। मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने इन धमाकों को 'तीव्र और व्यापक' बताया। इज़रायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने कहा कि उसने ईरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाते हुए समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इज़राइली सेना के अनुसार, हवाई हमलों में तेहरान के हथियार निर्माण केंद्रों और पश्चिमी ईरान में मिसाइल भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया। एक अलग बयान में आईडीएफने कहा कि उसकी वायु सेना ने मध्य ईरान के यज़्द में स्थित 'मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंगों के उत्पादन की प्रमुख सुविधा' पर भी हमला किया। सेना का दावा है कि यह केंद्र ईरानी नौसेना के मिसाइल और

समुद्री माइंस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। आईडीएफ के अनुसार, तेहरान में हमले बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन से जुड़े ठिकानों पर केंद्रित थे, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में इज़राइली वायु सेना ने मिसाइल लॉन्चर और भंडारण स्थलों को नष्ट किया।

इन कार्रवाइयों को इज़रायल ने ईरान की सैन्य क्षमताओं के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा बताया है। इसी बीच, संघर्ष के तेज होने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के बाद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरान की लगभग 90 प्रतिशत मिसाइल क्षमता और उसकी नौसेना व वायुसेना के बड़े हिस्से को निष्क्रिय कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान बातचीत से इनकार करता है तो अमेरिका सैन्य दबाव जारी रखेगा। उन्होंने ईरान को 'कमजोर लड़ाके लेकिन अच्छे वार्ताकार' बताया, हालांकि ईरान ने अमेरिकी वार्ता प्रयासों को बार-बार खारिज किया है।

कतर और अमेरिका ने रक्षा ऊर्जा सुरक्षा पर की चर्चा

वॉशिंगटन। कतर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल-थानी ने वॉशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रेज़री सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात कर रक्षा सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में हो रहे बदलावों पर चर्चा की है। यह बैठक पश्चिम एशिया में हो रहे ताजा घटना म और स्ट्रेट ऑफहोर्मुज में व्यवधान के बीच गुरुवार को आयोजित की गयी। दोनों पक्षों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति पर विचार-विमर्श करते हुए ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों देशों ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन देने के लिए कतर से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। बैठक में अमेरिका और कतर के बीच घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग पर भी चर्चा हुई तथा विशेष रूप से वर्तमान क्षेत्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार किया गया।

दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलाव और ऊर्जा संबंधी चिंताओं के बीच रणनीतिक समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

शेख मोहम्मद ने समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

रायपुर में आईपीएल 2026 के मुकाबले: आरसीबी के दो मैच, दर्शकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं

रायपुर। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर क्रिकेट के बड़े आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने दो घरेलू मुकाबले यहां स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार, आरसीबी का पहला मुकाबला 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ और दूसरा 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। टूर्नामेंट के शेष लीग मैच 13 अप्रैल से 24 मई के बीच आयोजित किए जाएंगे। इन मुकाबलों में विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के मैदान में उतरने की संभावना है, जिससे दर्शकों में खासा उत्साह है। वहीं केकेआर के मैच को लेकर टीम

के सह-मालिक शाहरुख खान के रायपुर आगमन की भी चर्चा है। मैचों के मददेनज़र स्टेडियम में दर्शकों की सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। विशेष रूप से गोल्ड और प्रीमियम श्रेणी की सीटों में सुधार के साथ-साथ वीआईपी दर्शकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीमित स्थान के बावजूद कुछ नई वीआईपी सीटें जोड़ने की तैयारी है ताकि अधिक संख्या में दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आयोजकों के अनुसार, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। लोकप्रिय खिलाड़ियों, विशेषकर विराट कोहली की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री करेंगे कुंवरगढ़ महोत्सव का भव्य शुभारंभ, 133 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

धरसीवा /मूक पत्रिका

स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने धरसीवा में बीते शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 31 मार्च 2026 को कुंवरगढ़ महोत्सव का भव्य आगाज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के कर-कमलों से किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र को ?133 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात भी मिलेगी।

विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि कुंवरगढ़ महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र की गौरवशाली विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कुंरा नगर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह क्षेत्र राजा कुँवर सिंह गोंड की समृद्ध विरासत से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसे 'कुँवरगढ़' के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 12 हजार की आबादी वाला यह क्षेत्र आज भी अपनी परंपरा और विकास के बीच संतुलन बनाए हुए है।

उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान ?133 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए नव निर्मित नवीन तहसील कार्यालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा।

महोत्सव में स्थानीय हस्तशिल्प, व्यंजन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

विधायक ने कहा कि यह महोत्सव क्षेत्र में भाईचारे और समरसता का संदेश देगा तथा कुंवरगढ़ की पारंपरिक पहचान को नई पीढ़ी से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की।उन्होंने यह भी बताया कि आयोजन के दौरान सुरक्षा और पार्किंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।प्रेस वार्ता में जनपद पंचायत अध्यक्ष शकुंतला ढिलेन्द्र सेन, उपाध्यक्ष दिनेश खुटे, नगर पंचायत कुंरा अध्यक्ष गोविंद साहू सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने पीएम आवास 2.0 में तेजी लाने, 30 अप्रैल तक सभी लंबित आवास पूर्ण करने के दिए निर्देश

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगरीय निकायों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री महोबे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावों की स्थिति, स्वीकृति एवं प्रेषण की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रस्तावों को शीघ्र तैयार कर तत्काल राज्य शासन प्रेषित किया जाए। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 30 अप्रैल तक लंबित आवासों को हर हाल में पूरा किया जाए।

कलेक्टर ने स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जांजगीर एवं चांपा नगरीय निकायों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसे जनभागीदारी के साथ अभियान के रूप में संचालित किया जाए, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित हो। उन्होंने गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने एवं शत-प्रतिशत अपशिष्ट प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब स्वच्छता सैनिक घर-घर कचरा संग्रहण के लिए आएं, तो नागरिक उन्हें सहयोग प्रदान करें तथा उन्हें धन्यवाद कर उनके कार्य के प्रति आभार व्यक्त करें। इसके साथ ही उन्होंने आकांक्षीय शौचालय, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक में सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

आर टी ई राशि वृद्धि की मांग पर निजी स्कूलों का राज्य स्तरीय असहयोग आंदोलन शुरू

आर टी ई राशि वृद्धि की मांग पर निजी स्कूलों का राज्य स्तरीय असहयोग आंदोलन शुरू, शिक्षा मंत्री व अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

शासन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही हैं

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिला बेमेतरा ने शिक्षा के अधिकार (आर टी ई) के अंतर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार आर टी ई की राशि नहीं बढ़ाती, तब तक निजी स्कूल शासकीय कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉ. अवधेश पटेल एवं सचिव रामकुमार भारती ने बताया कि 1 मार्च 2026 को आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। यह आंदोलन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीसी /4988/2025 के आदेश दिनांक 19 सितंबर 2025 के अनुपालन तक जारी रहेगा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले में एकमत निर्णय प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता एवं प्रदेश सचिव मोतीचंद जैन के आह्वान पर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष डॉ. अवधेश पटेल के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारियों द्वारा इस निर्णय को एकमत से स्वीकार किया गया। इस निर्णय को संरक्षक दीपक अरोरा, डॉ. अलका तिवारी, विनीत राजोरिया, योगेश बागरेचा, मृदु महाजन, वसीम खान, कृष्ण कुमार सोनी, राजेशधर दीवान, वीरेंद्र जायसवाल, शक्तिधर दीवान, लोकेश राठी, आनंद शर्मा, महेश केडिया, बी एस द्विवेदी, पी.एस. राजपूत, प्रकाश जैन, दिव्यम शुक्ला, विवेक तिवारी, विनय वर्मा, अमित ठाकुर, जितेंद्र राजपूत, रेवाराम पाल, अखिलेश शर्मा, जितेंद्र मिश्रा सहित साजा, बेरला, नवागढ़ एवं बेमेतरा ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों ने एकमत से स्वीकार किया। सरकारी कार्यों से पूर्ण असहयोग संगठन ने घोषणा की है कि निजी स्कूल शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल प्राचार्यों के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, विभाग द्वारा जारी पत्र, नोटिस एवं आदेशों का जवाब नहीं देंगे आर टी ई के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन कार्य में भाग नहीं लेंगे सरकारी कार्यक्रमों के लिए बसें भी नहीं मिलेंगी आंदोलन को और प्रभावी बनाते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक आर टी ई की प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि नहीं होती, तब तक निजी स्कूल किसी भी सरकारी कार्यक्रम, परीक्षा या अन्य गतिविधियों हेतु अपनी बसें उपलब्ध नहीं कराएंगे। सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि स्कूल शिक्षा विभाग गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा पर होने वाले व्यय के प्रति संवेदनहीन बना हुआ है तथा न्यायालय के आदेश और प्रदेशव्यापी आंदोलन की अनदेखी की जा रही है। शासन व जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन इस संबंध में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के साथ-साथ बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी जी. आर. चुर्वेदी को भी ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। स्पष्ट चेतावनी एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक असहयोग आंदोलन जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर शासकीय कार्यों में सहयोग नहीं किया जाएगा।

खनिज आवंटन में पारदर्शिता की मांग तेज ई-नीलामी प्रक्रिया पर उठे सवाल

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले में खनिज पट्टा आवंटन को लेकर अब सवालों का तूफान उठने लगा है। जिला पंचायत सदस्य विनोद भारद्वाज ने खनिज शाखा को पत्र लिखकर ई-नीलामी प्रक्रिया से जुड़े पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संचालनालय भौतिकी एवं खनिजकर्म, रायपुर के आदेश क्रमांक 50/त्रश्वहस्/686/2026 दिनांक 05 जनवरी 2026 के तहत चिन्हित ब्लॉकों के संबंध में कई गांवों में खनिज पट्टा आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई गांवों में आवंटन, पर जानकारी अधूरी! खैरहा , कुटेला, दुर्गापाली, खम्हारडीह, चंदाई, जुनाडीह, रापागुला , हरिहरपाली, भोजपुर, पचपेड़ी, भैंसदेहान , गाताडीह,सुलौनी सहित अन्य ग्रामों में खनिज पट्टा आवंटन हुआ है। लेकिन इन ग्रामों के प्रभावित लोगों को अभी तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ता जा रहा है।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई पूरी जानकारी-विनोद भारद्वाज ने साफशब्दों में कहा है कि सभी संबंधित ग्रामों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने खनिज विभाग से ई-नीलामी की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, चयन और आवंटन की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

प्रशासन पर बढ़ा दबाव-इस मुद्दे के उठने के बाद अब जिला प्रशासन और खनिज विभाग पर पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव बढ़ गया है। यदि समय रहते स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, तो यह मामला और गरमा सकता है।

जनता का सवाल - क्या नियमों का हुआ पालन?-स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है, तो फिर जानकारी देने में देरी क्यों? आखिरकार जनता को उनके क्षेत्र में हो रहे खनिज कार्यों की जानकारी मिलना उनका अधिकार है।अब सभी की निगाहें खनिज विभाग पर टिकी हैं कि वह इस मामले में कितनी पारदर्शिता दिखाता है और कब तक पूरी सच्चाई सामने आती है।

'सामुदायिक भवन पर 'जाति का कब्जा'! निजी जमीन, शासकीय निर्माण और बंद दरवाजे–मानिकपुर का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, प्रशासन पर उठे बड़े सवाल'

बरमकेला /मूक पत्रिका

देश जहां एक ओर समानता, अधिकार और संविधान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर गांवों की जमीन पर आज भी भेदभाव की सच्चाई सामने आ रही है। जनपद पंचायत बरमकेला अंतर्गत ग्राम पंचायत पिक्रिमाल के आश्रित ग्राम मानिकपुर में घटी एक घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यह मामला अब सिर्फएक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है।मानिकपुर गांव में सरकारी राशि से बना सामुदायिक भवन, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों के लिए समान उपयोग सुनिश्चित करना था, आज विवादों के घेरे में है। इस भवन के बाहर ÷माली समाज भवन÷ लिख दिया गया है और उस पर ताला जड़ दिया गया है। इस कदम ने गांव के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है।पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें इस भवन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। उनका कहना है कि यह केवल एक इमारत पर कब्जा नहीं, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों और सम्मान का खुला उल्लंघन है। ग्रामीणों के अनुसार, इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि गांवों में आज भी छुआछूत और जातिगत भेदभाव की मानसिकता खत्म नहीं हुई है।ग्रामीणों ने बताया कि इस गंभीर मामले को लेकर उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत दी। ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में निराशा और गुस्सा दोनों बढ़ते चले गए।जब स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला, तो पीड़ितों ने आखिरकार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में पहुंच चुका है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि ग्रामीण अब अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।इस पूरे मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विधानसभा क्षेत्र का है। ऐसे में प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक जिम्मेदारी दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मंत्री के क्षेत्र में ही इस तरह का भेदभाव सामने आ रहा है, तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। गांव में इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। स्ट/स्ज समुदाय के लोग इसे अपने अधिकारों पर सीधा हमला मान रहे हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।पीड़ितों की मुख्य मांग है कि सामुदायिक भवन से ÷माली समाज भवन÷ का बोर्ड हटाया जाए, भवन को सभी वर्गों के लिए खोला जाए और इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब पूरा मामला प्रशासन और न्यायालय के सामने है। यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में न्याय कितनी जल्दी और किस रूप में मिलता है।

यह घटना सिर्फ मानिकपुर गांव की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है–जो यह दिखाती है कि आज भी समानता की लड़ाई अधूरी है।

कलेक्टर-एसपी ने स्वच्छता अभियान चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश, स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने जिला मुख्यालय जांजगीर के रमन नगर में आज मुख्य नहर स्वच्छता अभियान में शामिल होकर नागरिकों को जागरूक किया। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, हसदेव के हीरो के वालिटियर्स, एनएसएस, एनसीसी, कृषि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं सहित नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं विभिन्न स्थानों पर सफाई कार्य करते हुए स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। अभियान के माध्यम से शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें अपने आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखने की अपील की। कलेक्टर-एसपी ने अभियान में भाग लेकर सड़क, नहर के किनारे साफ-सफाई की तथा लोगों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। अभियान के दौरान गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं छात्र-छात्राओं सहित नागरिकों ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया।

आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक बदलाव भी

साहस, आत्मविश्वास और मेहनत की मिसाल : ग्राम मनियारी की महिलाओं ने लिखी सफलता की नई कहानी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के ग्राम मनियारी की महिलाओं ने अपने साहस, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है। यह कहानी केवल कुछ महिलाओं की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की कहानी बन चुकी है। यह दर्शाती है कि यदि सही अवसर, मार्गदर्शन और दृढ़ निश्चय हो, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है।

संघर्ष से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा

इस कहानी की शुरुआत अनुसूया साहू से होती है, जो बचपन से ही सिलाई कार्य में कुशल थीं। उनके पास हुनर तो था, लेकिन आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी इस कला को आगे नहीं बढ़ा पा रही थीं। घर की जिम्मेदारियों और सीमित आय के चलते उनका अधिकांश समय घरेलू कार्यों में ही बीत जाता था। उनके मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा तो थी, लेकिन परिस्थितियां उनका साथ नहीं दे रही थीं।

महतारी वंदन योजना बनी उम्मीद की किरण-मार्च 2024 में महतारी वंदन योजना की शुरुआत उनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई। इस योजना के तहत उन्हें हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि मिलने लगी। जहां अधिकांश लोग इस राशि को दैनिक खर्चों में उपयोग कर लेते हैं, वहीं अनुसूया साहू ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पैसे को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने लगातार छह महीनों तक इस राशि को सुरक्षित रखा और अंततः एक सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन मिलने के बाद उन्होंने अपने घर से ही काम शुरू किया। शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे ऑर्डर जैसे कपड़ों की मरम्मत और सामान्य सिलाई का काम मिलने लगा, लेकिन उनकी मेहनत और काम की गुणवत्ता के कारण लोगों का विश्वास बढ़ता गया।

एक महिला की पहल से बना महिलाओं का समूह-अनुसूया साहू की इस पहल ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। विशेष रूप से ओमकारेश्वरी साहू, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थीं, उन्होंने भी उनसे संपर्क किया। अनुसूया के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से उन्होंने भी सिलाई सीखना शुरू किया और कुछ समय बाद अपनी सिलाई मशीन खरीदकर इस कार्य से जुड़ गईं। धीरे-धीरे यह छोटा प्रयास एक समूह में बदल गया। गांव की अन्य महिलाएं ङ्क पार्वती, गंगा और हेमिनी ङ्क भी इस पहल से जुड़ गईं। इन महिलाओं ने अनुसूया से सिलाई का प्रशिक्षण लिया और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। इन सभी महिलाओं के बीच सहयोग, एकता और सीखने की भावना ने इस कार्य को और मजबूत बना दिया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सरकारी योजनाओं का मिला सहयोग-इस पूरी प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में जानकारी दी और उनका पंजीकरण करवाया। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदने और अपने काम को आगे बढ़ाने में किया। सरकारी योजनाओं के सही उपयोग और जागरूकता के कारण इन महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला और उनका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया।

आज सफल सिलाई केंद्र चला रही हैं पांच महिलाएं-आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ये पांचों महिलाएं मिलकर एक सफल सिलाई केंद्र चला रही हैं। वे महिलाओं के लिए ब्लाउज, सूट और बच्चों के कपड़ों के साथ-साथ पुरुषों के कपड़े भी तैयार कर रही हैं। उनके काम की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी के कारण गांव और आसपास के क्षेत्रों में उनकी अच्छी पहचान बन गई है।

आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक बदलाव भी-इस कार्य से होने वाली आय ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। अब वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए भी निवेश कर रही हैं। पहले जहां वे केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, वहीं अब वे परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं।

अन्य महिलाओं के लिए बन रही हैं प्रेरणा-सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महिलाओं का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान काफी बढ़ गया है। वे अब समाज में एक नई पहचान बना चुकी हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। गांव की कई अन्य महिलाएं भी अब उनसे प्रेरित होकर कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

सरकारी योजनाओं के सही उपयोग से बदल सकती है जिंदगी-यह कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग, आपसी सहयोग और दृढ़ निश्चय से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अनुसूया साहू और उनकी साथियों ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं यदि ठान लें, तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए वरदान बनी 'PM RAHAT' योजना: सारंगढ़-बिलाईगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा ?.5 लाख तक मुफ्त इलाज

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली असामयिक मृत्यु को रोकने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'PM RAHAT' योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब दुर्घटना के पहले 'गोल्डन आवर' (दुर्घटना के बाद का पहला 60 मिनट सबसे निर्णायक होता है। यदि इस अवधि के भीतर पीड़ित को उचित चिकित्सा उपचार मिल जाए, तो उसके जीवित बचने की संभावना सबसे अधिक होती है और स्थायी विकलांगता का जोखिम काफी कम हो जाता है)में पीड़ित को बिना किसी अग्रिम भुगतान के उच्च स्तरीय उपचार मिल सकेगा।

क्या है PM RAHAT योजना

यह एक राष्ट्रीय कैशलेस आपातकालीन उपचार योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है,कि वित्तीय अभाव के कारण किसी भी सड़क दुर्घटना पीड़ित की जान न जाए। जिले की किसी भी सड़क

(राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय मार्ग या ग्रामीण सड़क) पर होने वाली दुर्घटना के पीड़ित इस योजना के पात्र हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं: कैशलेस उपचार: दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख तक का निःशुल्क इलाज।गोल्डन आवर पर फोकस: दुर्घटना के तुरंत बाद मिलने वाली चिकित्सा को प्राथमिकता।

त्वरित सहायता: आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 के माध्यम से एम्बुलेंस और नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल की जानकारी।

बिना पहचान के भी इलाज: यदि पीड़ित के पास आयुष्मान कार्ड या पहचान पत्र न भी हो, तब भी तत्काल उपचार शुरू किया जाएगा।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी प्रमुख शासकीय अस्पतालों और चिन्हांकित निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है।

1. समस्त शासकीय अस्पताल:
जिला अस्पताल, सारंगढ़।
समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) - बिलाईगढ़, बरमकेला आदि।
सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)।

2. चिन्हांकित निजी अस्पताल (आयुष्मान/PM-JAY से संबद्ध):

जिले के वे प्रमुख निजी अस्पताल जो पूर्व से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वे इस योजना में भी सेवाएं देंगे।

मुख्य रूप से शामिल हैं:

1. श्री राधाकृष्ण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल सारंगढ
2. पटेल हॉस्पिटल एव डायग्नोस्टिक सेंटर बरमकेला
3. ए. डी. वैष्णव स्मृति चिकित्सालय भटगांव
4. आर.एस.एम. हॉस्पिटल बंधापली सारंगढ

कैसे काम करेगी यह व्यवस्था

दुर्घटना की सूचना मिलते ही 112 की टीम पीड़ित को नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल पहुंचाएगी। अस्पताल को पुलिस वेरिफिकेशन (दृष्टिक पोर्टल के माध्यम से) 24 से 48 घंटों के भीतर प्राप्त हो जाएगा।

जिससे अस्पताल को भुगतान की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके लिए मरीज को अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बस्तर मैराथन के विजेताओं को अब तक नहीं मिला पुरस्कार, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

जगदलपुर/मूक पत्रिका

बस्तर हैरिटेज मैराथन के विजेता खिलाड़ियों को अब तक पुरस्कार राशि नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने राजीव भवन जगदलपुर में प्रेसवार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सुशील मौर्य ने कहा कि बस्तर मैराथन जैसे बड़े आयोजन में प्रदेश सहित विदेशों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन विजेताओं को आज तक उनकी पुरस्कार राशि नहीं दी गई है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे छत्तीसगढ़ की छवि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार और जिला प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग की है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार पिछले दो वर्षों में प्रदेश भर में इवेंट के नाम पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन खिलाड़ियों को भुगतान करने में लापरवाही बरती जा रही है। मौर्य ने आशंका जताई कि कहीं आयोजन में राशि का उपयोग केवल प्रचार-प्रसार तक सीमित तो नहीं रह गया।

कांग्रेस नेता ने बस्तर ओलंपिक सहित अन्य आयोजनों को भी ÷सरकारी इवेंट÷ बताते हुए कहा कि सरकार विकास कार्यों की बजाय प्रचार में अधिक रुचि ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा और कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दिया जा रहा है।

कानून व्यवस्था को लेकर भी मौर्य ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार इस पर नियंत्रण पाने में विफल रही है।

प्रेसवार्ता में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, गौरनाथ नाग, कोमल सेना, रविशंकर तिवारी, अभिषेक नायडू, जाहिद हुसैन, नीतीश शर्मा, जावेद खान, शादाब अहमद, अफ्रोज बेगम सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बदहाली की भेंट चढ़ा अमृत सरोवर, सरकार की योजना पर पानी फेर रहे हालात

रायगढ़/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत पुसौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत तेलीपाली के आश्रित ग्राम जामपाली में अमृत सरोवर सौंदरीकरण लाखो की लागत से वर्ष 2024-24 में निर्मित अमृत सरोवर आज बदहाली की दास्तां बयां कर रहा है। दरअसल, जिस उद्देश्य से यह तालाब, जल संरक्षण और ग्रामीण सौंदर्यीकरण के लिए तैयार किया गया था, वह अब उपेक्षा का शिकार हो चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गावों की खुशहाली पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना की नीव रखी थी। लेकिन मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी हैं। अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही आज बदहाली का कारण

बन गया है। वर्तमान समय में इन अमृत सरोवर की दशा काफी खराब है। अमृत सरोवर तालाब जामपाली आबादी से दूर लगभग 7,04820 रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। तालाब की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां पानी नाममात्र है और जो मौजूद है वह भी गंदगी से भरा हुआ है। चारों ओर बेतरतीब घास और झाड़ियां उगी हुई हैं, जिससे यह सरोवर वीराना जैसा प्रतीत होता है। सरकार की मंशा थी कि यह स्थान सिर्फ शराबीयो का अड्डा बन गया है

ग्रामीणों ने लगाया आरोप

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और तालमेल की कमी रही है। सरोवर की सफाई, पानी की भरपूर उपलब्धता और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के कंधों पर थी, उनकी अनदेखी ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को हास्यास्पद बना दिया है।

ग्रामीणों ने जताई चिंता

गौरतलब है कि जल संरक्षण के लिए बनी यह योजना अब स्वयं पानी को तरस रही है।

गांव के विकास और पर्यावरण सुधार की दृष्टि से बनाई गई यह परियोजना अगर ऐसे ही उपेक्षा की शिकार रही, तो सरकारी धन की बर्बादी और ग्रामीणों के साथ छल के अलावा यहां कुछ नहीं बचेगा। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि बरजी गांव के अमृत सरोवर की बदहाल स्थिति की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि योजना का असली उद्देश्य सफल हो सके।

आरटीआइ का उड़ रहा मखौल, कैसे खुलेगी पोल

पुसौर/मूक पत्रिका

मामला पुसौर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटेभण्डार का है जहाँ आवेदक के द्वारा 23/01/2026 को ग्राम पंचायत छोटेभण्डार मे बने सामुदायिक शौचालय से सम्बंधित जानकारी चाही गई थी लेकिन 30 दिन की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद आज दिनाक तक आवेदक को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम का अफसर मखौल उड़ा रहे हैं। पंचायत से मांगी गई जन सूचना उपलब्ध कराने में खूब मनमानी की जा रही है। जानकारी देने का जनसूचना अधिकारी को नहीं है समय. सूचना न मिलने से विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी उजागर नहीं हो पाता है। सूत्र की मानें तो आरटीआइ दाखिल होने पर घोटालों की परत दर परत खुलने का भय अफसरों को सताने लगता है। यही कारण है कि आरटीआइ मे जानकारी देने से अफसर कतराते हैं।

महीनों करना पड़ता है इंतजार-आरटीआइ के तहत सरकारी विभाग से जनसूचना के लिए आवेदन करने पर सूचनाकर्ता को दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है। जनसूचना न मिलने पर पुनः रिमाइंडर भेजने के बाद भी आरटीआइ मिलने की राह देखनी पड़ती है। ऐसे में विभागों को विकास व कल्याणकारी योजनाओं के लिए मिले बजट, कराए गए कार्य, भुगतान व अन्य बिंदुओं की जानकारी नहीं मिल पाती है।

थलसेना के अग्निवीर हेतु ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

भारतीय थल सेना द्वारा अग्निवीर सैनिक के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु अविवाहित इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से 1 अप्रैल 2026 तक थलसेना के वेबसाईट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन (www.joinindianarmy.nic.in) के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन व आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। अग्निवीर सैनिक भर्ती अंतर्गत जनरल ड्यूटी तकनीकी, ऑफिस असिस्टेंट, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस एवं नियमित कैडर भर्ती, धर्म गुरू, नर्सिंग सहयोगी तथा हवलदार एसएसी के पदों भर्ती की जाएगी। जिसके लिए ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन जून 2026 में संभावित है। भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय व राज्यकीय शिक्षा बोर्ड व संस्था से कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं, आटीआई, इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की ऊंचाई, वजन, सीना विभिन्न पदों हेत अलग-अलग है। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट हेतु ऑनलाईन परीक्षा के समय टाईपिंग टेस्ट भी देना होगा। उम्मीदवार को चयन हेतु कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। भर्ती की विस्तृत जानकारी थल सेना के वेबसाईट सेना भर्ती कार्यालय शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम के पास नवा रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212, 2965214 तथा कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अधिकारी रामजीत राम से मोबाइल नंबर 9424184279 से प्राप्त कर सकते हैं ।

कांकेर के 'जनसहयोग' ने पेश की मानवता की मिसाल: राजस्थान से आए साधुओं का किया भव्य स्वागत और सेवा

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ :-कांकेर अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए पहचानी जाने वाली नगर की सुप्रसिद्ध समाजसेवी संस्था ÷जनसहयोग÷ ने एक बार फिर अपनी सेवा भावना से सबका दिल जीत लिया है। राजस्थान के अलवर से आए साधुओं के एक दल की सहायता और सम्मान कर संस्था ने 'अतिथि देवो भव' की परंपरा को जीवंत कर दिया है। जैसे ही 'जनसहयोग' के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी को यह जानकारी मिली कि अलवर (राजस्थान) से साधुओं का एक बड़ा दल कांकेर पहुँचा है, उन्होंने बिना देर किए अपनी टीम के साथ साधुओं का पता लगाया। संस्था के सदस्यों ने न केवल साधुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि उनके ठहरने और भोजन की भी उत्तम व्यवस्था की। सेवा के इस क्रम में जनसहयोग संस्था द्वारा साधुओं को भोजन कराने के साथ-साथ वस्त्र और अन्न का दान भी किया गया। जब संस्था को ज्ञात हुआ कि साधुओं के इस दल का अंतिम पड़ाव दंतेवाड़ा है, तो उनकी आगे की यात्रा सुगम बनाने के लिए अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी ने अपनी टीम की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। संस्था के सदस्यों ने साधु-संतों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

अलवर निवासी जिन साधु-संतों का सत्कार किया गया उनमें प्रमुख रूप से रामदास जी, गोपाल दास, पन्ना दास, बालक दास, लहरी दास, संगकारा दास, लक्ष्मण दास, पाल दास, करण दास, नाथूदास, छोटे दास और मेहर दास शामिल थे। साधु-सेवा के इस पुनीत कार्य में अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी के साथ डॉ. श्याम देव, करण नेताम, मनोज दुबे, आशुतोष देव, अक्षय और राजेश चौहान ने सक्रिय भूमिका निभाई। नगर के प्रबुद्ध जनों और श्रद्धालुओं ने 'जनसहयोग' के इस सराहनीय कदम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।

युवासेना ने जुआ-सट्टा और नशे के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ कांकेर शिवसेना की युवा इकाई युवासेना ने जिले में बढ़ते अवैध जुआ-सट्टा और नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। युवासेना के प्रदेश महासचिव हर्ष शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में बताया गया कि जिले में आईपीएल (Indian Premier League) शुरू होने से पहले ही सट्टा माफिया और खाईवाल सक्रिय हो गए हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जुआ-सट्टा का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। साथ ही मटका-सट्टा और अवैध नशे का धंधा भी जिले में खुलेआम चल रहा है, जिससे कई परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। युवासेना के सानिध्य शर्मा ने बताया कि जुआ-सट्टा और नशे के कारण कई परिवारों को पलायन तक करना पड़ रहा है।

उन्होंने पुलिस प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले में उचित और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। युवासेना ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई, तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान सानिध्य शर्मा, इन्द्रजित भंडारी, समृद्ध शर्मा, श्लोक नेताम, निखिल पांडे, देवकुमार टेमरे, आकाश सेन, शुभम सहारे, सुजित नेताम, संतोष यादव 50 और वैभव पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

टुकड़ों में काटकर बेचने वाले बन गए करोड़पति, एसडीएम ने मांगा प्रतिवेदन

रायगढ़ में बेशकीमती जमीन पर चल रहा गोरखधंधा, एक ओर सरकारी जमीन, दूसरी ओर कोटवारी जमीन पर कब्जा गढ़उमरिया और बांजीनपाली

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ में अब बेरोजगार भूमाफियाओं को रोजगार देने के लिए अलग तरह की योजना चलाई जा रही है। उनको सरकारी जमीनें और कोटवारी जमीनें बेचने की खुली छूट दी जा रही है ताकि वे परिवार का पालन-पोषण कर सकें। बड़ी सफाई से गढ़उमरिया में सरकारी जमीन और बांजीनपाली में कोटवारी जमीन टुकड़ों में बेच दी गई। राजस्व अमला केवल तमाशबीन बनकर देखता रहा।स्वरोजगार के अवसर हर क्षेत्र में हैं। रायगढ़ में यदि कोई धंधा सबसे ज्यादा तेजी से फला-फूला है तो वह जमीनों का कारोबार ही है। जमीन सरकारी हो या निजी, बड़ी आसानी से प्लॉट काटकर बेचे जा सकते हैं। राजस्व अमला भी खुलकर इसमें मदद करेगा। सरकार की फ्लैगशिप योजना की तरह सरकारी जमीनें और आवंटन जमीनें बिकवाई जा रही हैं। सहदेवपाली, छातामुड़ा, गढ़उमरिया, सांगीतराई, अमलीभौना, अतरमुड़ा, कौहाकुंडा, बोईरदादर, संबलपुरी सभी

जगहों पर सरकारी जमीनें बेची जा चुकी हैं। जहां बेच नहीं सके, वहां नक्शे में हेराफेरी करके निजी जमीन में दबा दी गई। अब जो मामला आया है, उसमें कई नए खुलासे हो रहे हैं। संस्कार स्कूल पुलिया के आगे रोड के दोनों तरफ की जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है। कुछ में मकान बन चुके हैं तो कुछ में बन रहे हैं। इससे बेखबर राजस्व विभाग नींद में है। दाहिनी ओर रायगढ़ तहसील का बांजीनपाली आता है। यहां करीब 11 एकड़ कोटवारी जमीन है। इसमें से दो-तीन एकड़ पर 45 मकान बन चुके हैं और आगे की तैयारी भी चल रही है। मजे की बात यह है कि कुछ लोगों ने मकान बनाकर किराए पर भी दे दिया है। कोटवार को खेती करने के लिए दी गई जमीन पर प्लॉट काटकर बेच दिए गए। खसरा नंबर 204, 220, 221, 222, 226/2, 229, 231, 234/4, 235, 85, 96, 99 कुल रकबा 4.182 हे. है। यह पूरी जमीन बांजीनपाली की ग्राम नौकर सेवा भूमि है।

सेंट्रल वेयर हाउस की जमीन तक पहुंचा अतिक्रमण-रोड के दूसरी तरफ बह रहा पुराना नाला बहुत जल्द जमीन से गायब हो जाएगा। जिस गति से यहां नाला किनारे कॉलम खड़ा करके मकान बनाए जा रहे हैं, उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। पुल पर खड़ा होकर देखें तो दूर-दूर तक अवैध कब्जे ही दिखते हैं। यहां खनं 16/1 रकबा 1.1870 हे. शासकीय भूमि है। इस पर अतिक्रमण हो चुका है। आजू-बाजू की दूसरी जमीनों पर भी निर्माण शुरू हो चुका है। यहीं पर शासकीय भूमि खनं 97/1 रकबा 2.0070 हे. पर भी अवैध कब्जे होने लगे हैं। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को आवंटित भूमि 97/2 रकबा 2.0190 हे. का कुछ हिस्सा भी अतिक्रमण की जद में आ चुका है।

पूर्व में चला है प्रकरण-ऐसा भी नहीं है कि राजस्व विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया विभाग में चलती है, उससे भूमाफियाओं को ही ताकत मिल रही है। महीनों तक नोटिस और उसका जवाब लिया जाता है। इस बीच निर्माण चलता रहता है। पटवारी प्रतिवेदन में अवैध कब्जा प्रमाणित होने के बाद भी सख्त कार्रवाई नहीं होती।

जब तक तहसील न्यायालय में आदेश होता है, तब तक दोगुनी संख्या में मकान बन जाते हैं। बांजीनपाली और गढ़उमरिया दोनों मामलों में प्रतिवेदन सौंपा गया था।

संपादकीय

जंग में जब सप्लाई रुकती है, तब शुरू होता है असली संकट

भारत सहित कई देश साफतौर पर किसी भी मसले का हल युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए निकालने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जंग में शामिल देश कई बार इस सबसे जरूरी तकाजे को समझने में देर कर देते हैं। किसी भी युद्ध में भले ही दो देश या पक्ष शामिल होते हैं, लेकिन संभव है कि उसके नतीजों का दायरा इतना बड़ा हो कि अन्य कई देशों के लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी हो जाएं। मसलन, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद न केवल पश्चिम एशिया में, बल्कि समूची दुनिया में कई स्तर पर मुश्किलें बढ़ती देखी जा सकती हैं। यह छिपा नहीं है कि ऊर्जा या तेल और गैस के लिए बहुत सारे देश अपनी जरूरतों के ज्यादातर हिस्से के लिए मध्यपूर्व पर निर्भर हैं। मगर इस युद्ध की शुरुआत के बाद अब धीरे-धीरे स्थितियां बिगड़नी शुरू हो चुकी हैं।हालांकि भारत सहित कई देश साफतौर पर किसी भी मसले का हल युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए निकालने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जंग में शामिल देश कई बार इस सबसे जरूरी तकाजे को समझने में देर कर देते हैं। दोतरफा व्यापक हमलों और उसमें जानमाल के भारी नुकसान के बीच ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, तब से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति भी सीमित या बहुत कम हो गई है। यह ऐसी मुश्किल है, जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे।समस्या यह है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचा, तो आम लोगों के सामने बहुस्तरीय संकट खड़े होंगे और सरकार के सामने चुनौतियां गहराएंगी। आने वाले दिनों में युद्ध के स्वरूप के बिगड़ने और इसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने 'अप्रत्याशित चुनौतियां' हैं। जाहिर है, अब जो हालात हैं, उसमें इनका सामना करना ही विकल्प है। ऐसे में सरकार को जहां रोजमर्रा की अनिवार्य जरूरतों की आपूर्ति को संतोषजनक स्तर पर बनाए रखने के लिए हर उपाय करना होगा, वहीं विपरीत स्थितियों में भी भरोसे को बनाए रखना होगा।शायद इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखला का संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया।

भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर संसद में नेतृत्व तक का लंबा सफर तय किया है, फिर भी सच्ची समानता अभी भी दूर है। मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और महिला आरक्षण विधेयक एक बड़ी छलांग का वादा करता है। लेकिन लैंगिक भेदभाव, परोक्ष राजनीति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी व्यवस्थागत बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। विश्व स्तर पर भारत में महिलाओं की स्थिति मिश्रित है, जहाँ वे नेतृत्व और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं लैंगिक असमानता, सुरक्षा और श्रम भागीदारी में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और साक्षरता में प्रगति के बावजूद, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और आर्थिक असमानता प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। जो महिलाओं की स्थिति में चिंताजनक गिरावट दर्शाता है।

महिलाओं को लेकर डॉ कलाम का सपना अधूरा

(योगेंद्र योगी)

आर्थिक भागीदारी में भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में केवल 18 प्रतिशत है, जो काफी कम है। कामकाजी महिलाओं में से केवल 40-42 प्रतिशत ही अपने पति के बराबर या उससे अधिक कमाती हैं। साक्षरता दर में 2010-2021 के बीच 14.4प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम मशहूर रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की ओर ले जाता है। जब महिला सुखी होती है, तो घर सुखी होता है। जब घर सुखी होता है, तो समाज सुखी होता है, और जब समाज सुखी होता है, तो राज्य सुखी होता है, और जब राज्य सुखी होता है, तो देश में शांति होती है और उसका विकास अधिक गति से होता है। देश महिलाओं की मौजूदा हालात को देखते हुए लगता यही है डॉ कलाम का यह सपना पूरा नहीं हुआ है। इस सपने को पूरा करने के लिए अभी शायद दशकों तक इंतजार करना पड़ेगा।

भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर संसद में नेतृत्व तक का लंबा सफर तय किया है, फिर भी सच्ची समानता अभी भी दूर है। मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और महिला आरक्षण विधेयक एक बड़ी छलांग का वादा करता है। लेकिन लैंगिक भेदभाव, परोक्ष राजनीति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी व्यवस्थागत बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। विश्व स्तर पर भारत में महिलाओं की स्थिति मिश्रित है, जहाँ वे नेतृत्व और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं लैंगिक असमानता, सुरक्षा और श्रम भागीदारी में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और साक्षरता में प्रगति के बावजूद, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और आर्थिक असमानता प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। जो महिलाओं की स्थिति में चिंताजनक गिरावट दर्शाता है।

देश में महिलाएं अभी तक लिंगभेद का शिकार हैं। महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और अपराधों के ग्राफ बताते हैं कि उनकी तरक्की ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। साल 2023 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2023 में महिलाओं के खिलाफ 13,366 मामले दर्ज हुए, जो मुंबई में 6,025 और बेंगलुरु में 4,870 से कहीं ज्यादा हैं। हालांकि साल 2022 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। देश में 2021 से 2023 के बीच महिलाओं के खिलाफ कुल 13,21,745 अपराध दर्ज हुए। औसतन हर तीन मिनट में एक महिला किसी न किसी अपराध का शिकार हुई। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में पेश आंकड़ों के बताया कि ने घरेलू हिंसा, अपहरण, यौन अपराध और बाल शोषण जैसी घटनाओं में लगातार तीन वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई।

उत्तर प्रदेश इन तीन वर्षों में सबसे आगे रहा, जहां 1,88,207 मामले दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में 1,31,958, राजस्थान 1,31,246, बंगाल 1,05,313 और मध्य प्रदेश में 95,780 मामलों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। महिलाओं के

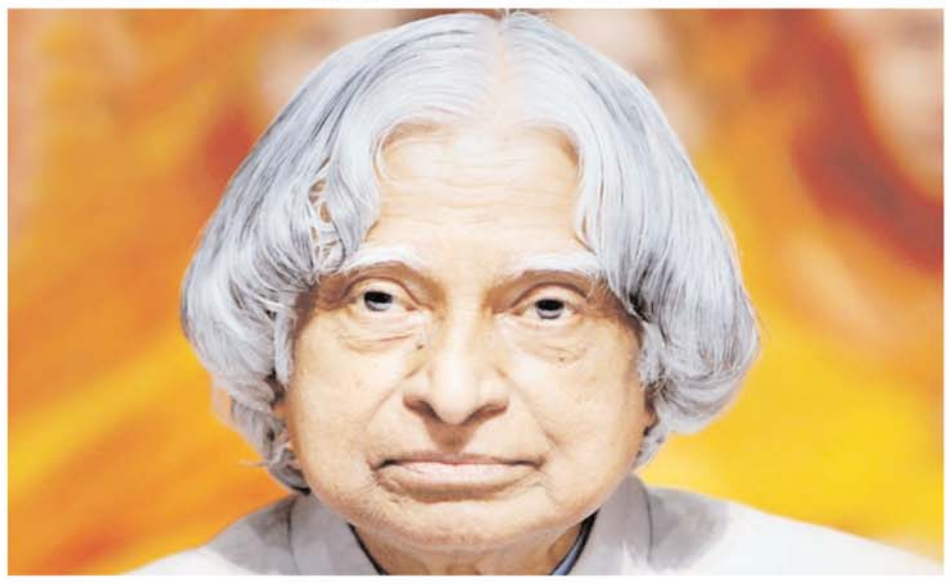

खिलाफ प्रमुख अपराधों में शामिल रहे पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 4,09,929 मामले तो वहीं अपहरण के 2,49,284 मामले सामने आए। गृह राज्य मंत्री बंदी ने बताया था कि अपराधों के ये रुझान सामाजिक और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करते हैं। विभिन्न राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों से जुड़े अपराधों की संख्या चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है।

आर्थिक भागीदारी में भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों (82 प्रतिशत) की तुलना में केवल 18 प्रतिशत है, जो काफी कम है। कामकाजी महिलाओं में से केवल 40-42प्रतिशत ही अपने पति के बराबर या उससे अधिक कमाती हैं। साक्षरता दर में 2010-2021 के बीच 14.4प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालाँकि, केवल 10प्रतिशत महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय खुद ले पाती हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2024 में 800 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। फिर भी, वैश्विक स्तर पर यह भागीदारी अभी भी कम है।

लोकनीति-सीएसडीएस के 2019 के 'महिलाएं और राजनीति' सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकतर महिलाओं को रैलियों में जाने, उम्मीदवार से मिलने या चुनाव प्रचार करने के लिए परिवार की मंजूरी लेनी पड़ती है। 58 प्रतिशत महिलाओं का मानना था कि राजनीतिक परिवार से आने वाली महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश आसान होता है। जबकि 57 प्रतिशत का मानना था कि आर्थिक रूप से मज़बूत परिवारों की महिलाओं को बढ़त मिलती है। अपने सर्वोच्च स्तर पर भी पहुंचकर भी महिलाओं का लोकसभा में हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत ही रहा, जबकि मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है। 1952 में पहली लोकसभा में सिर्फ़ 22 महिलाएं चुनी गई थीं। 1977 में तो यह संख्या घटकर 19 ही रह गई। एक बड़ा बदलाव 21वीं सदी में दिखा। साल 2009 में 59 महिलाएं सांसद बनीं, 2014 में यह संख्या बढ़कर 62 हो गई, और 2019 में यह ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 78 तक पहुंच गई। 2024 में यह थोड़ा घटकर 74 रह गई। राजनीतिक दल अक्सर कम टिकट देने को यह कहकर सही ठहराते हैं कि महिलाओं के जीतने की संभावनाएं कमज़ोर होती हैं। लेकिन सफलता का आंकड़ा इस दावे को सवालों के घेरे में डाल देता है। 1957 में 49 प्रतिशत महिला उम्मीदवार जीतीं, जबकि पुरुषों में जीत का प्रतिशत सिर्फ़ 33 प्रतिशत था। 1962 में महिलाओं की सफलता दर 47 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की सिर्फ़ 25 प्रतिशत। हाल के चुनावों में भी महिलाओं की सफलता दर बराबर या थोड़ा बेहतर ही रही। वर्ष 2019 में 11 प्रतिशत जीतीं, जबकि पुरुषों में यह दर 6 प्रतिशत थी। 2024 में महिलाओं की सफलता दर 9 प्रतिशत और पुरुषों की 6 प्रतिशत रही। इन आंकड़ों से साफ़ है कि जब महिलाओं को टिकट मिलता है तो वे चुनाव जीत सकती हैं। चाहे महिलाएं अब वोटिंग में लगभग बराबरी पर हों, लेकिन असली राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है। महिला आरक्षण बिल का पारित होना इस अंतर को कम करने का एक संरचनात्मक रास्ता ज़रूर खोलता है। आज भी 23न युवा महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, जो ग्रामीण और गरीब घरों में अधिक आम है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 46प्रतिशत है, हालांकि, उनकी प्रभावी भागीदारी कम बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में, जहां अक्सर पुरुष रिश्तेदार निर्णय लेने में हावी रहते हैं। इस प्रथा को उजागर करने और इसकी निंदा करने के लिए 'प्रधान पति' शब्द राजनीतिक शब्दावली में शामिल हो गया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार गहरी जड़ें जमा चुके लैंगिक मानदंड प्रगतिशील कानूनों को कमजोर कर सकते हैं - परिवार और समुदाय सत्ता में महिलाओं को देखकर असहज महसूस कर सकते हैं, इसलिए वे पुरुषों को पर्दे के पीछे रखकर पुराने मानदंडों को लागू करते हैं। महिलाएं अब सेना, अंतरिक्ष, खेल और व्यावसायिक नेतृत्व में नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। स्व-सहायता समूह, डिजिटल साक्षरता और शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों से बदलाव आ रहा है।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तलाशने की बढ़ी दरकार

(उमेश चतुर्वेदी)

भारत के संदर्भ में देखें, तो रसोई गैस के मोर्चे में देश ने पिछले दस वर्षों में बड़ी क्रांति को देखा है। देश के रसोई घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की खपत बढ़ी है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, देश में प्राकृतिक गैस की रोजाना खपत करीब 189 मिलियन घन मीटर है।

ईरान पर अमेरिकी और इजरायली कार्रवाई के बाद पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में ना सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया को कई तरह की परेशानियों और रूकावटों का सामना करना पड़ रहा है। अगर खाड़ी संकट जल्द नहीं थमा तो पहले से ही करीब अस्सी अरब डॉलर सालाना खर्च करने वाले भारत की ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। पेट्रोलियम कारोबार पर निगाह रखने वाले वैश्विक संस्थानों को आशंका है कि अगर ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध लंबा खिंचा और इससे कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल दस डॉलर की भी बढ़ोत्तरी हुई तो भारत का पेट्रोलियम आयात खर्च पंद्रह हजार करोड़ डॉलर सालाना बढ़ सकता है। पेट्रोलियम आयात पर होने वाली इस बढ़ोतरी के चलते भारत पर नए सिरे से आर्थिक दबाव बढ़ेगा । ऐसे में जरूरी है कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर नए सिरे से विचार करे और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश की दिशा में ना सिर्फ आगे बढ़े, बल्कि शोध और विकास पर भी जोर लगाए।

खाड़ी संकट के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को इस दिशा में सोचने को मजबूर किया है। तमाम देश वैचारिक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्पों की खोज में जुटने लगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर दुनिया का बढ़ता ध्यान इसी बदलते सोच का प्रतीक है। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर पिछले कुछ वर्षों में इतना जोर दिया है कि वहां एक तरह से इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति ही आ गई है। भारत ने साल 2030 तक कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तीस प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ईरान संकट के पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों से सालाना पेट्रोलियम आयात में करीब 25 हजार करोड़ की बचत होने लगी है। लेकिन जिस तरह पेट्रोलियम उत्पादक खाड़ी के क्षेत्र में हालात बदल रहे हैं, उससे देश को पेट्रोलियम के विकल्प ढूंढ़ने की दिशा में तेजी लाने और इस सिलसिले में शोध और विकास को भी गति देने की जरूरत बढ़ी है। ऐसा किए बिना देश के लिए पेट्रोल और डीजल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के भारी खर्च पर लगाम लगाना आसान होगा।

भारत के संदर्भ में देखें, तो रसोई गैस के मोर्चे में देश ने पिछले दस वर्षों में बड़ी क्रांति को देखा है। देश के रसोई घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की खपत बढ़ी है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, देश में प्राकृतिक गैस की रोजाना खपत करीब 189 मिलियन घन मीटर है। लेकिन घरेलू उत्पादन महज 97.5 मिलियन घन मीटर रोजाना ही है। करीब साठ फीसद गैस बाहर से आयात ही करना पड़ता है। देश में करीब 33 लाख एलपीजी कनेक्शन हैं। इनमें दस लाख 33 हजार कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। इन कनेक्शनों पर सालाना 312 लाख टन गैस खर्च होती है। इस खर्च होने वाली गैस का साठ फीसद हिस्सा आयात किया जाता है। जाहिर है कि देश का बड़ा गैस खर्च भी आयात पर ही निर्भर है। इसमें दो राय नहीं कि आधुनिक दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ ही हैं, जिसमें डीजल, पेट्रोल और गैस तीनों ही शामिल हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की ऊर्जा स्रोत के रूप में सबसे ज्यादा खपत डीजल की है, जो कुल पेट्रोलियम खर्च का करीब करीब 38.5 फीसद है। इसके बाद पेट्रोल का नंबर आता है, जिसकी कुल ऊर्जा स्रोत के खपत में करीब 18 प्रतिशत की भागीदारी है, जबकि तीसरे नंबर पर करीब चौदह फीसद हिस्सेदारी के साथ प्राकृतिक गैस है।

टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत के सशक्त प्रयासों से बढ़ती उम्मीदें

टीबी जैसी गंभीर बीमारी 21वीं सदी में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज इसके प्रभावी इलाज उपलब्ध होने के बावजूद लोग इसके लक्षणों (दो सप्ताह से अधिक खांसी, खांसी में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, तेजी से वजन घटना, भूख कम लगना, सीने में दर्द और सांस फूलना इत्यादि) को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं। इसके साथ ही, आज भी समाज में टीबी को लेकर कलंक बना हुआ है।

(डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत)

नई तकनीक को तेजी से अपनाने, सेवाओं को लोगों के पास तक पहुँचाने (डीसेंट्रलाइजेशन) और बड़े स्तर पर जनभागीदारी के कारण भारत में टीबी मरीजों की पहचान और इलाज में काफी सुधार हुआ है। 2015 में जहाँ केवल 53 प्रतिशत मरीज इलाज तक पहुँच पाते थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 92 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है।

हर साल, हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। यह कार्यक्रम 24 मार्च 1882 की तारीख को याद करने का दिन है जब जर्मन फिजिशियन डॉ. रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, यह जीवाणु तपेदिक/क्षय रोग (टीबी) का कारण बनता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज हो जाने से टीबी के निदान और इलाज में बहुत आसानी हुई। जर्मन फिजिशियन रॉबर्ट कोच की इस खोज के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यही कारण है कि हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी के सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक नतीजों पर दुनिया में जन-जागरूकता फैलाने और दुनिया से टीबी के खात्मे की कोशिशों में तेजी लाने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस मनाता आ रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज के सौ साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहली बार 24 मार्च 1982 को विश्व क्षय रोग दिवस शुरू मनाने की शुरुआत की, तभी से हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है।

टीबी जैसी गंभीर बीमारी 21वीं सदी में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज इसके प्रभावी इलाज उपलब्ध होने के बावजूद लोग इसके लक्षणों (दो सप्ताह से अधिक खांसी, खांसी में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, तेजी से वजन घटना, भूख कम लगना, सीने में दर्द और सांस फूलना इत्यादि) को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं। इसके साथ ही, आज भी समाज में टीबी को लेकर कलंक बना हुआ है। कई लोग इस डर से जांच कराने से बचते हैं कि कहीं उनकी बीमारी का पता चलने पर सामाजिक बहिष्कार का सामना न करना पड़े। यही सामाजिक धारणा टीबी नियंत्रण और उन्मूलन की राह में एक बड़ी बाधा है और इसके कारण भारत देश में मामलों की संख्या अधिक बनी रहती है। ऐसे में सबसे अधिक आवश्यकता है व्यापक जन-जागरूकता की, ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसका पूरा उपचार संभव है। भारत सरकार द्वारा देशभर में चलाए जा रहे विभिन्न प्रभावी अभियानों के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखने लगे हैं, जो इस दिशा में उम्मीद की किरण प्रस्तुत करते हैं।

क्षयरोग उन्मूलन की दिशा में भारत की टीबी मुक्त भारत के नाम समर्पित यात्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत देश ने 2015 से 2024 तक क्षय रोग (टीबी) के मामलों में उल्लेखनीय 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, यह दर वैश्विक औसत गिरावट 12 प्रतिशत की लगभग दोगुनी है। साल 2015 में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 237 लोगों को ये बीमारी थी जो 2024 में 21 प्रतिशत घटकर प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 187 हो गई है। यह वैश्विक स्तर पर टीबी मामलों में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है, जो अन्य टीबी के उच्च-भार वाले देशों में देखी गई कमी से भी अधिक प्रभावशाली है। हालांकि ये आंकड़े अब भी देश से टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य से काफी दूर हैं। टीबी से होने वाली मौतों में भी भारत देश में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 21 हो गई है। यह टीबी से होने वाली मौतों को कम करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है, जो सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता और प्रभावी नीतियों के परिणामस्वरूप संभव हो सकी है। देश में इस रोग की रोकथाम के लिए किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

नई तकनीक को तेजी से अपनाने, सेवाओं को लोगों के पास तक पहुँचाने (डीसेंट्रलाइजेशन) और बड़े स्तर पर जनभागीदारी के कारण भारत में टीबी मरीजों की पहचान और इलाज में काफी सुधार हुआ है। 2015 में जहाँ केवल 53 प्रतिशत मरीज इलाज तक पहुँच पाते थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 92 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। 2024 में करीब 26.18 लाख मरीजों की पहचान होने का अनुमान है, जबकि कुल अनुमानित मामले लगभग 27 लाख हैं। इसका मतलब है कि पहले जो मिसिंग केस यानी ऐसे मरीज जो टीबी से ग्रसित थे लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आते थे, उनकी संख्या 2015 में लगभग 15 लाख थी, जो अब घटकर 2024 में एक लाख से भी कम रह गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इलाज की सफलता दर बढ़कर लगभग 90 प्रतिशत हो गई है, जो दुनिया के औसत 88 प्रतिशत से भी बेहतर है। हमारे भारत देश में पूरे विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा टीबी मरीजों की संख्या है। भारत देश का लगभग 26 प्रतिशत टीबी बीमारी के मामलों में पूरे विश्व में योगदान है। आज के समय पर दवा-प्रतिरोधी टीबी बड़ी चिंता का विषय है, जिसमें वैश्विक मामलों का लगभग 32 प्रतिशत हिस्सा भारत से आता है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत में दवा-प्रतिरोधी टीबी की रोकथाम और प्रभावी उपचार एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। हालांकि भारत देश में ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के मरीजों की उपचार सफलता दर जो साल 2020 में 68 प्रतिशत थी वह 2024 में 77 प्रतिशत हो गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीबी मरीज को सही समय पर इलाज नहीं मिलता है तो एक सक्रिय टीबी मरीज साल में कम से कम 10-15 नए मरीज पैदा करता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मरीज से होने वाला संक्रमण भी ड्रग रेजिस्टेंट ही होता है जो कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। इसलिए जरूरी है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मरीजों की विशेष निगरानी की जानी चाहिए और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी प्राथमिकता के आधार पर जांच करायी जानी चाहिए, जिससे कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मरीज दूसरे ड्रग रेजिस्टेंट मरीज पैदा नहीं कर सकें।

उपमुख्यमंत्री ने 4.08 करोड़ रूपए की लागत के सकरी नदी तटबंध निर्माण का किया भूमिपूजन

3नदी में तटबंध निर्माण से सुरक्षित होंगे घर- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर/मूक पत्रिका

सकरी नदी में कटाव को रोकने और ग्रामीणों को बाढ़ से सुरक्षा देने के उद्देश्य से आज ग्राम कोडार में 4.08 करोड़ रुपए की लागत से 250 मीटर लंबे तटबंध निर्माण कार्य का भूमिपूजन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना से ग्राम कोडार के नदी किनारे बसे मकान सुरक्षित होंगे, कटाव की समस्या पर नियंत्रण मिलेगा और ग्रामीणों को निस्तारी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम रेगाखार पंचायत के आश्रित ग्राम कोडार में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सकरी नदी के किनारे लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस तटबंध निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि 250 मीटर लंबा यह तटबंध न केवल नदी के कटाव को रोकेगा, बल्कि बाढ़ के दौरान पानी के दबाव से होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। इससे नदी किनारे बसे घर सुरक्षित रहेंगे और लोगों को बार-बार होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। साथ ही, नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों के लिए निस्तारी की सुविधाएं भी बेहतर होंगी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम में 142 आवास स्वीकृत किए गए हैं और सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार ने अपने वादे के अनुरूप गठन के साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक में आवास योजना को स्वीकृति देकर इसे प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ गांव में ही आसानी से मिल सके, इसके लिए ग्राम पंचायत भवन में डिजिटल सुविधा केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष सुविधा मिल रही है। साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 25 किस्तों में 25 हजार रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जा चुकी है, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके और गांवों का समग्र विकास हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी इस योजना को क्षेत्र के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे किसानों और आम ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने भी इस पहल पर खुशी जताते हुए शासन और उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। तटबंध निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद सकरी नदी के किनारे बसे ग्राम कोडार के लोगों को कटाव और बाढ़ की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नितेश अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, संतोष पटेल, विजय पटेल, वीरसिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

28 और 29 मार्च को अवकाश में भी खुला रहेगा रजिस्ट्री ऑफिस

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

नागरिकों को रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी रजिस्ट्री ऑफिस शनिवार 28 मार्च, रविवार 29 मार्च तथा मंगलवार (महावीर जयंती) 31 मार्च को भी सामान्य कार्यदिवसों की तरह खुले रहेंगे। इन तिथियों में दस्तावेजों के पंजीयन सहित अन्य सभी संबंधित सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगी।शासन के इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपने लंबित पंजीयन कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनज़र इन दिनों में पंजीयन कार्यों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

सारंगढ़ में सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 7.30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़ नगर में सड़क दुर्घटना से बचाव एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया है। जारी आदेश अनुसार सारंगढ़ में सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 7.30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री देवांगन ने कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 61.82 लाख की लागत से निर्मित रैन बसेरा का किया लोकार्पण

मरीजों व परिजनों के लिए आवास सुविधा का हुआ विस्तार

रायपुर/मूक पत्रिका

वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री देवांगन ने कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 61.82 लाख की लागत से निर्मित रैन बसेरा का किया लोकार्पण, वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा आज कोरबा स्थित स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एसईसीएल के सीएसआर मद से 61.82 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वसुविधायुक्त आश्रयालय का लोकार्पण किया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री देवांगन ने कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 61.82 लाख की लागत से निर्मित रैन बसेरा का किया लोकार्पण , कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 4.50 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तर क्षमता वाला क्रिटिकल केयर यूनिट 16.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण होगा। इसी प्रकार कैजुअल्टी भवन के ऊपरी तल पर 100 बिस्तरों वाले नए वार्ड का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपये में जारी है। गर्मी से मरीजों व परिजनों को राहत दिलाने के उद्देश्य से अस्पताल में 83 एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 40 बिस्तरों की क्षमता वाला आई वार्ड लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से जल्द प्रारंभ किया जाएगा। नवजात शिशुओं हेतु 6 बिस्तरों का विशेष वार्ड तैयार किया गया है।

साथ ही सीएसआर एवं डीएमएफ फंड से सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके बाद जिलेवासियों को अत्याधुनिक उपचार सुविधाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि नए आश्रयालय (रैन-बसेरा) के शुरू होने से मरीजों के परिजनों को ठहरने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

मिनी गार्डन का लोकार्पण, सड़क डिवाईडर प्लांटेशन जनसेवा में हुआ समर्पित

उद्योग मंत्री ने कोलमैन की प्रतिमा का किया अनावरण

रायपुर/मूक पत्रिका

प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज शुक्रवार को उद्योग मंत्री ने कोलमैन की प्रतिमा का अनावरण किया। सिविल लाईन में मिनी गार्डन का लोकार्पण भी किया गया। इसी प्रकार पुष्पलता उद्यान के सामने सड़क डिवाईडर प्लांटेशन जनसेवा में समर्पित हुआ। इस अवसर पर महापौर मती संजूदेवी राजपूत उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर की व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ शहर का सौदर्यीकरण कर इसे संजाने, संवारने की दिशा में नित नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं, एक ओर जहां शहर की स्वच्छता पर पूरा फोकस रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर थीम आधारित पेंटिंग, चित्रकारी, लघु उद्यानिकी थीम आधारित रोड साईड प्लांटेशन पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा दर्री बराज पुल के समीप कोलमैन की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। इसी प्रकार निगम द्वारा सिविल लाईन में निगम आयुक्त के बंगले के समीप मिनी गार्डन बनाया गया है, जिसका लोकार्पण भी उद्योग मंत्री व महापौर के करकमलों से सम्पन्न हुआ। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर के रोड डिवाईडरों में मल्टीकलर फूलों के पौधे रोपित कर डिवाईडरों को मल्टीकलर फूलों से सजाने संवारने का कार्य भी हो रहा है, इस कड़ी में निगम द्वारा सुभाष चौक पुष्पलता उद्यान से कोसाबाड़ी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रोड डिवाईडर में इमोजी थीम के अंडाकार गमलों में वोगनबेलिया तथा यूफारबिया मल्टीकलर फूलों के पौधे लगाये गये हैं, इन्हें भी आज जनसेवा में समर्पित किया गया। इस मौके पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, पार्षद अशोक चावलानी, अजय गोंड़, पंकज देवांगन, वैभव शर्मा, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश वास्तव, मनोज सिंह राजपूत, अनिल यादव, उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर, सहायक अभियंता राहुल मिश्रा, अरूण मिश्रा आदि के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारीगण व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (तीसरा दिन) कर्नाटक का दबदबा कायम

रायपुर/मूक पत्रिका

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तीसरे दिन कर्नाटक ने अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। कर्नाटक 10 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला राज्य बन गया है। तीसरे दिन के अंत तक कर्नाटक को कुल 13 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक हो गए हैं, जिनमें सभी स्वर्ण पदक तैराकी स्पर्धाओं से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के स्टार तैराक मणिकांता एल ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरे दिन दो स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किए। अब तक वे कुल आठ स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता के सबसे सफल खिलाड़ी बन चुके हैं और कर्नाटक की बढ़त को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पदक तालिका में ओडिशा 6 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि असम 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ त्रिपुरा के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर बना हुआ है। मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य के लिए एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। अनुष्का भगत ने महिलाओं की 50 मीटर बेकस्ट्रोक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना तीसरा रजत हासिल किया, जबकि निखिल जाल्को ने पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में कांस्य पदक जीता।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम जैतपुरी को दी 2.98 करोड़ रुपए के नवीन विद्युत उपकेंद्र की सौगात

रायपुर/मूक पत्रिका

रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम जैतपुरी में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी सौगात देते हुए 2 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 के.व्ही., 5 एम.वी.ए. क्षमता के नवीन विद्युत उपकेन्द्र का विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस उपकेन्द्र के स्थापित होने से जैतपुरी सहित आसपास के 12 गांवों के करीब 1 हजार 750 से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण, नियमित एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। वर्षों से लो वोल्टेज, बार-बार बिजली बाधित होने और लंबी फीडर लाइन की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने ग्राम जैतपुरी में 5 लाख 20 हजार रुपए के सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार गांव और वनांचल क्षेत्रों के विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि यह नया बिजली उपकेन्द्र बनने से क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर होगी और विकास तेजी से बढ़ेगा। अब लोगों को लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिजली व्यवस्था स्थायी रूप से बेहतर हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस उपकेन्द्र में 5 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा तथा यहां से 3 अलग-अलग 11 केवी फीडर निकाले जाएंगे, जिससे आसपास के 12 गांव सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस व्यवस्था से क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या दूर होगी, जिससे किसानों को विशेष रूप से राहत मिलेगी और कृषि कार्य के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण सदस्य भगत पटेल, नितेश अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जनपद उपाध्यक्ष नंद वास, लोकचंद साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। विकासखंड कवर्धा के ग्राम जैतपुरी में नवीन 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारंभ होने से क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्रवासियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करेगी।

बकरा पकड़ते देख ग्रामीणों ने समझा संदिग्ध, एक रायपुर रेफर, दूसरा बीजापुर में भर्ती

अफवाह बनी आफत: बच्चा चोर समझकर दो युवकों की बेरहमी से पिटाई

समाज ने सौंपा ज्ञापन, पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया। ग्राम दंपाया के दो युवकों को संदिग्ध समझकर ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट दिया। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक को हालत नाजुक होने पर रायपुर रेफर किया गया है, जबकि दूसरे का इलाज जिला अस्पताल बीजापुर में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास कावटी और संतोष कावटी अपने रिश्तेदारी गांव मुत्तापुर से बकरा खरीदकर लौट रहे थे। नदी पार करते समय बकरा अचानक छूट गया, जिसे पकड़ने के लिए दोनों युवक उसके पीछे दौड़े। इसी दौरान बंगापल्ली गांव के कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया और बिना किसी पुष्टि के लाठी-डंडों से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, घटना के समय करीब 20-25 लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने दोनों युवकों को घेरकर जमकर मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी धक्का-मुक्की की गई।

बाद में कुछ पहचान वाले लोगों के हस्तक्षेप से स्थिति संभली और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल संतोष कावटी एक शासकीय कर्मचारी हैं और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं। घटना के बाद परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मद्देड़ थाना प्रभारी डी.पी. पात्रे ने बताया कि घटना गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे की है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक बकरा खरीदकर लौट रहे थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और मामला हिंसा में बदल गया। मामले में पुलिस ने 20-25 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

समाज ने दी चेतावनी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

घटना के विरोध में मरार समाज जिला इकाई बीजापुर ने थाना मद्देड़ में लिखित शिकायत सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दोनों युवक निर्दोष थे और केवल बकरा लेकर लौट रहे थे, लेकिन अफवाह के चलते उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

पुलिस की अपील: अफवाहों पर न करें भरोसा

इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने आम लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी या किडनी चोरी जैसी खबरें अधिकांशतः भ्रामक होती हैं और समाज में डर फैलाने का काम करती हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, लेकिन खुद कानून हाथ में न लें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले संदेशों को बिना सत्यापन के आगे न बढ़ाएं, क्योंकि ऐसी अफवाहें कई बार निर्दोष लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती हैं।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका को होर्मुज की नाकाबंदी करनी चाहिए', पूर्व एनएसए बोल्टन का बड़ा बयान

वॉशिंगटन, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से

फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के तेल राजस्व को खत्म करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करनी चाहिए। जॉन बोल्टन ने आकलन किया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत में क्षेत्रीय संघर्ष और ईरानी ऊर्जा पर भारत की निर्भरता पर बात हुई होगी। जॉन बोल्टन ने कहा, 'मुझे लगता है कि पीएम मोदी की सोच साफ है कि वे ईरान से तेल खरीदने के इच्छुक हैं। आज सुबह दो भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से निकले भी हैं। हालांकि इस लेन-देन का असर भू-राजनीति पर पड़ता है।' बोल्टन ने कहा कि 'इस तरह राजस्व का प्रवाह क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और इससे ईरान को राजस्व मिलता है और उसकी युद्ध मशीन चलती रहती है।' 'अमेरिका को होर्मुज की नाकाबंदी करनी चाहिए' जॉन बोल्टन ने कहा, 'पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में भारत की ऊर्जा जरूरतों को ईरान की बजाय एक स्थायी स्त्रोत पर स्थानांतरित करने पर भी बात हुई होगी।' बोल्टन ने कहा कि 'अमेरिका को ईरान के राजस्व स्त्रोतों को बाधित करने की जरूरत है और इसके लिए मुझे लगता है कि अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करनी चाहिए ताकि ईरान का निर्यात बाधित हो।' दोनों नेताओं की बातचीत ऐसे समय हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए पांच दिनों के संघर्ष विराम का एलान किया है। मंगलवार को पीएम मोदी ने भी राज्यसभा में पश्चिम एशिया के हालात पर सरकार का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने समुद्री और प्रवासी हितों की रक्षा के लिए अपनी राजनयिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगा है और इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा।

तेल बाजार में सट्टेबाजी; इनसाइडर ट्रेडिंग के संकेत

लंदन/ वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर संभावित हमले टालने की घोषणा से ठीक पहले तेल बाजार में असामान्य सट्टेबाजी का मामला सामने आया है। बीबीसी द्वारा समीक्षा किए गए डाटा से पता चलता है कि घोषणा से करीब 15 मिनट पहले अचानक भारी मात्रा में ट्रेडिंग हुई, जिससे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट का कुछ ट्रेडर्स ने बड़ा फायदा उठाया। इस घटनाक्रम ने इनसाइडर जानकारी के दुरुपयोग की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। सुबह 06:49 ईटी पर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (एनवाईमेक्स) पर डब्ल्यूटीआई क्रूड के 733 कॉन्ट्रैक्ट्स पर दांव लगाए गए थे, जो महज एक मिनट में बढ़कर 2007 हो गए। यह करीब 170 मिलियन डॉलर यानी 1,400 करोड़ रुपये के सौदों के बराबर था। इसी तरह ब्रेंट क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक मिनट के भीतर 20 से बढ़कर 1600 से ज्यादा ट्रेड दर्ज किए गए, जिनकी कीमत 150 मिलियन डॉलर यानी 1245 करोड़ आंकी गई। सामान्यत: सोमवार सुबह इस समय इतनी बड़ी ट्रेडिंग नहीं होती, जिससे इस गतिविधि पर संदेह और गहरा गया। जिन ट्रेडर्स ने पहले से दांव लगाया था, उन्हें भारी मुनाफा हुआ।
एक्सएनालिस्ट्स के मुख्य तेल विश्लेषक मुकेश साहदेव ने इस ट्रेडिंग पैटर्न को स्पष्ट रूप से असामान्य बताया। उनके अनुसार उस समय अमेरिका और ईरान के बीच किसी गंभीर बातचीत के संकेत नहीं थे, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में तेल गिरने पर दांव लगाना स्वाभाविक नहीं लगता।

लेबनान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया, दोनों देशों के संबंध बिगड़े

लेबनान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष हर दिन और भी भयानक रूप ले रहा है। अमेरिका और इस्त्राइल के हमलों से क्षेत्र में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, वहीं ईरान भी खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों की गड़गड़ाहट के बीच यह संघर्ष अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि अमेरिका एक विशाल बिजली उत्पादन संयंत्र को निशाना बनाने वाला था, लेकिन बातचीत को ध्यान में रखते हुए यह हमला टाल दिया गया। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बेरूत में ईरान के राजदूत को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित किया। उन्हें सप्ताह के अंत तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों का स्पष्ट संकेत है। इससे लेबनान में तेहरान और हिजबुल्लाह की भूमिका पर तनाव बढ़ गया है। यह फैसला 2 मार्च को इस्त्राइल-हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होने के बाद आया है। प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा, ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड

लेबनान में हिजबुल्लाह के अभियान चला रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लेबनानी सरकार इस टकराव में शामिल नहीं होना चाहती थी। सलाम ने कहा कि खामेनेई की हत्या का बदला लेना लेबनानियों का कर्तव्य नहीं है।

कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत सिविल एविएशन प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि की है। प्रवक्ता अब्दुल्ला अल-राजही ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और नुकसान संपत्ति तक ही सीमित रहा। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और अन्य संबंधित एजेंसियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्व में भी धमाके सुनाई दिए। बमबारी के कारण कई आवासीय इमारतें और एक स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जॉर्डन की राजधानी अमान के दक्षिण में कम आबादी वाले इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने की घटना सामने आई। सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय के प्रवक्ता के अनुसार, किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। जॉर्डन के अधिकारी कहते हैं कि युद्ध की शुरुआत से अब तक देशभर में सैकड़ों मिसाइल टुकड़े गिर चुके हैं। सऊदी अरब ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के पूर्वी प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल और कम से कम छह ड्रोन को मार गिराया।

मौत के आंसू! आंखों से खून निकलने के बाद लड़की ने तोड़ा दम

न्यूयार्क। एक चमकती-दमकती आर्ट स्टूडेंट सोफी वार्ड की अचानक हुई मौत ने चिकित्सा जगत और आम लोगों के बीच डर पैदा कर दिया है। सोफी को शुरुआती लक्षण मामूली बुखार और सिरदर्द जैसे लगे लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी आंखों से खून बहने लगा और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाते, उसने दम तोड़ दिया। जांच में पता चला कि वह मेनिन्जाइटिस बी नाम के खतरनाक बैक्टीरियल इंफेक्शन का शिकार थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोफी को अचानक तेज सिरदर्द, शरीर में दर्द, रोशनी से चिड़चिड़ाहट और भारी थकान महसूस हुई। परिवार उसे अस्पताल ले गया लेकिन डॉक्टरों ने इसे सामान्य वायरल इंफेक्शन बताकर घर भेज दिया। रात भर में सोफी की हालत इतनी बिगड़ी कि अगली सुबह जब उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया तब तक उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। यह एक अत्यंत गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली में सूजन पैदा कर देता है। यह बीमारी इतनी घातक है कि संक्रमण के कुछ ही घंटों के भीतर यह जानलेवा साबित हो सकती है।

शांति वार्ता के बीच ट्रंप को ईरान से मिला रहस्यमयी तोहफा, बोले- ये तेल और गैस से जुड़ा महंगा गिफ्ट

वॉशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक चौंकाने वाला बयान दिया। ईरान के साथ युद्धविराम पर बातचीत की चर्चाओं के बीच ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने उन्हें एक बहुत बड़ा और काफी कीमती तोहफा भेजा है। हालांकि उन्होंने इस तोहफे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सिर्फ इतना कहा कि ये तोहफा तेल और गैस से जुड़ा है। ट्रंप जहां ईरान के साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं, वहीं ईरान की सेना अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रही है। दरअसल मंगलवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि ईरान की तरफ से जो लोग युद्धविराम पर बातचीत कर रहे हैं, क्या उन्हें उन पर विश्वास है? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, वे किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने ईरान से एक तोहफा मिलने का संकेत दिया। जिसके आधार पर ट्रंप ने कहा कि वे सही लोगों से बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है और वो तोहफा आज पहुंच गया है। यह एक बड़ा तोहफा है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि वह क्या है, लेकिन ये एक खास तोहफा है।' ट्रंप ने बताया कि यह तोहफा तेल और गैस से जुड़ा है। इसके अलावा ट्रंप ने ज्यादा जानकारी देने से

इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले पांच दिनों के लिए रोकने का एलान किया। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान की युद्धविराम को लेकर बात हो रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सरकार ने ईरान को 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव भेजा है। हालांकि ईरान की तरफ से इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच अमेरिका द्वारा पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। जिससे चर्चा है कि अगर युद्धविराम पर सहमति नहीं बनती है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी आक्रमण कर सकता है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ बातचीत होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी की सेना ने ट्रंप पर तंज कसा है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने ट्रंप के बातचीत के दावे का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि 'अपनी हार को समझौते का नाम देने की कोशिश न करें। आपके वादों के युग का अंत हो रहा है। दुनिया में अब दो मोर्चे हैं, जिनमें से एक सच्चाई का है और एक झूठ का। आपकी अंदरूनी लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि अब आप खुद से ही समझौते पर बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आपके निवेश पर कोई बात नहीं होगी, न ही आप भविष्य में तेल और गैस की पुरानी कीमतों को वापस देखेंगे। आपको ये समझना होगा कि इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता हमारी सेना के ताकतवर हाथों में है।'

ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, पर सिर्फ जेडी वेंस से करेगा बात

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया संकट के कूटनीतिक समाधान पर बातचीत चल रही है। इस बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को साफ संकेत दिया है कि वह अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के साथ दोबारा बातचीत नहीं करना चाहता। इसके बजाय तेहरान की प्राथमिकता अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत करने की है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया संस्थान सीएनएन ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का मानना है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के साथ बातचीत विश्वास की कमी के कारण प्रभावी नहीं होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ही ईरानी सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे और वह बातचीत विफल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, जेडी वेंस युद्ध खत्म करने के समर्थक हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वेंस, ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं थे। यही वजह है कि विटकॉफ, कुश्नर और यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तुलना में वेंस को संघर्ष खत्म करने के पक्ष में ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि उनकी कूटनीतिक टीम के सभी प्रमुख सदस्य वार्ता में शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'जेडी (वेंस), मार्को (रुबियो), जेरेड कुश्नर, स्टीव विटकॉफ और मैं खुद—सभी बातचीत प्रक्रिया में शामिल हैं।

ईरान युद्ध का झटका: नए घरों में सोलर पैनल और हीट पंप अनिवार्य, ब्रिटेन का फैसला

ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम

लंदन, एजेंसी। ईरान युद्ध से पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ब्रिटेन ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इंग्लैंड में बनने वाले सभी नए घरों में सोलर पैनल और हीट पंप अनिवार्य करने का एलान किया है, ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाई जा सके। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को नए नियम पेश करते हुए स्पष्ट किया कि यह कदम नीति-निर्माताओं की ओर से ईरान युद्ध के आर्थिक और ऊर्जा प्रभावों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के अनुसार, यह पहल फ्यूचर होम्स स्टैंडर्ड का हिस्सा है, जो 2028 से लागू होगा। इस मानक के तहत सभी नए घरों में ऑन-साइट रिन्यूएबल बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा की होगी। साथ ही, घरों में लो-कार्बन हीटिंग सिस्टम जैसे हीट पंप और हीट नेटवर्क को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा, ईरान युद्ध ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य जीवाश्म

ईंधन बाजारों की पकड़ से बाहर निकलना है, जिन पर देश का नियंत्रण नहीं है। मिलिबैंड ने यह भी बताया कि सरकार न केवल नए घरों में सोलर पैनल को मानक बना रही है, बल्कि आने वाले महीनों में दुकानों पर प्लग-इन सोलर पैनल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें लोग अपने घरों की बालकनी में आसानी से स्थापित कर सकेंगे।

ऊर्जा सुरक्षा बनाम घरेलू उत्पादन: इस फैसले को लेकर ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में भी बहस तेज हो गई है। विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी की शैडो एनर्जी सेक्रेटरी क्लेयर कुटिन्हो ने सरकार से नॉर्थ सी में नए तेल और गैस क्षेत्रों के लाइसेंस जारी करने की मांग की है, ताकि घरेलू ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाकर उपभोक्ताओं के बिल कम किए जा सकें। यह बहस इस बात को रेखांकित करती है कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशों के सामने दो विकल्प हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेज बदलाव या पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना।

अन्य देशों ने भी अपनाए सख्त उपाय: छुट्टी, राशनिंग और 'वर्क फ्रॉम होम' का सहारा एशियाई देशों ने सबसे तेजी से कदम उठाए हैं। श्रीलंका ने स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी, साथ ही क्यूआर कोड आधारित फ्यूल राशनिंग लागू कर दी। बांग्लादेश ने शिक्षा संस्थान बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी और रोजाना 5 घंटे की बिजली कटौती लागू की। भूटान ने जमाखोरी रोकने के लिए जरीकैन में ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान में चार दिन का वर्क वीक लागू।

टोक्यो में चीनी दूतावास में घुसने के आरोप में जापानी सैनिक गिरफ्तार, चीन ने जताया विरोध; मांगा जवाब

टोक्यो, एजेंसी। जापान के अधिकारियों ने बुधवार को एक जापानी सैनिक को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। इस सैनिक पर कथित रूप से टोक्यो में चीनी दूतावास में बिना इजाजत (अवैध रूप) से घुसने का आरोप है। चीन ने इस घटना पर विरोध जताया था, जिसके एक दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है। अब यह मामला जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव का नया केंद्र बन गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में एक मीडिया वार्ता के दौरान बताया कि मंगलवार सुबह एक व्यक्ति दीवार फांदकर दूतावास परिसर में जबरन घुस आया। उस व्यक्ति ने खुद को जापानी आत्म-रक्षा बल का अधिकारी बताया था। टोक्यो पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र 23 साल है और वह जापान की थल सेना (जीएसडीएफ) का सदस्य है।

जापानी सेना ने पुष्टि की है कि संदिग्ध सैनिक मियाजाकी प्रांत के कैंप एबिनो में तैनात है। सेना के अधिकारी इस मामले में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जापानी मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह सैनिक चीनी राजदूत को यह कहने के लिए दूतावास में घुसा था कि चीन जापान के प्रति अपना कड़ा रुख बंद करे। सैनिक के पास एक चाकू भी था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई, तो वह खुद को मार लेगा। जापान के सरकारी चैनल एनएचके के अनुसार, उस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया और आगे की जांच के लिए टोक्यो पुलिस को सौंप दिया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर दूतावास की दीवार फांदी थी और वहां एक चाकू भी मिला है।

चीन ने इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जताया है। प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि

जापान अपने सैनिकों को ठीक से नियंत्रित और अनुशासित करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि जापान ने चीनी दूतावास और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। चीन ने मांग की है कि जापान इस मामले की पूरी जांच करे, दोषी को सजा दे और चीन को इस पर स्पष्टीकरण दे।

जब दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। पिछले साल नवंबर में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा था कि ताइवान पर चीन की सैन्य कार्रवाई जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है और ऐसी स्थिति में बल प्रयोग की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद से ही चीन ने जापान के खिलाफ कूटनीतिक और व्यापारिक कड़े कदम उठाए हैं।

सऊदी प्रिंस सलमान को ईरान जंग से क्या फायदा: ट्रंप से कहा- युद्ध जारी रखें

वॉशिंगटन, एजेंसी। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार, युवराज का मानना है कि यह अमेरिका-इस्त्राइल के सैन्य अभियान के माध्यम से पश्चिम एशिया को फिर से आकार देने का एक ऐतिहासिक अवसर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध जारी रखने पर जोर पिछले सप्ताह हुई कई वार्ताओं में युवराज मोहम्मद ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया है कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार को समाप्त करने के लिए दबाव बनाना आवश्यक है। बातचीत से जुड़े लोगों का कहना है कि युवराज का तर्क है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक खतरा है, जिसे केवल वहां की वर्तमान सरकार को हटाकर ही समाप्त किया जा सकता है। इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को एक गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि इस्त्राइल शायद एक ऐसे ईरान को पसंद करेगा जो आंतरिक कलह में इतना उलझा हो कि वह इस्त्राइल के लिए खतरा न बने। वहीं, सऊदी अरब एक असफल ईरानी राज्य को अपने लिए एक गंभीर और सीधा सुरक्षा खतरा मानता है।

● अमेरिका फंस गया लंबी लड़ाई में?

विश्लेषकों का कहना है कि 'भले ही युवराज मोहम्मद युद्ध से बचना चाहते हों, लेकिन उन्हें चिंता है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप अब पीछे हटते हैं, तो सऊदी अरब और शेष पश्चिम एशिया को एक उग्र और क्रोधित ईरान का अकेले सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ईरान जलडमरूमध्य को समय-समय पर बंद करने की शक्ति भी हासिल कर सकता है। हालांकि सऊदी अरब जलडमरूमध्य के बंद होने से निपटने के लिए अन्य खाड़ी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, लेकिन यदि जलमार्ग जल्द ही नहीं खोला गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

सऊदी और अमेरिकी सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो ईरान सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर और भी विनाशकारी हमले कर सकता है। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध में फंस सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख सार्वजनिक तौर पर युद्ध को लेकर बदलता रहा है। कभी वे युद्ध के जल्द खत्म होने का संकेत देते हैं, तो कभी इसे और भड़कता हुआ बताते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके प्रशासन और ईरान के बीच हमारे दुश्मनी के पूर्ण और अंतिम समाधान के संबंध में उत्पादक बातचीत हुई है, हालांकि ईरान ने बातचीत की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। ईरान के साथ युद्ध के सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका-इस्त्राइल के हमलों के जवाब में ईरान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने पहले ही तेल बाजार में भारी व्यवधान पैदा कर दिया है। युवराज मोहम्मद के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। अमेरिकी अधिकारियों को सूचित किए गए लोगों के अनुसार, सऊदी नेता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यह केवल अस्थायी है। सऊदी अधिकारियों ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया है कि युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने युद्ध को लंबा खींचने का दबाव डाला है। सरकार के एक बयान में कहा गया है 'सऊदी अरब का साम्राज्य हमेशा से इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है, इससे पहले कि यह शुरू भी हुआ हो। हमारे अधिकारी ट्रंप प्रशासन के साथ निकट संपर्क में हैं और हमारी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। बयान में यह भी कहा गया है 'आज हमारी मुख्य चिंता अपने लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हो रहे दैनिक हमलों से खुद को बचाना है।

13 अप्रैल से 24 मई तक 50 मैच, 8 डबल हेडर; टोटल 74 मुकाबले ही होंगे

आईपीएल के सेकेंड फेज का शेड्यूल रिलीज

मुंबई। इंडियन प्रीमियर लीग के सेकेंड फेज का शेड्यूल रिलीज हो गया है। आईपीएल कमेटी ने शाम 6 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी। 13 अप्रैल से 24 मई तक 12 वेन्यू पर 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें 8 डबल हेडर होंगे।

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रायपुर को अपना दूसरा होमग्राउंड बनाया, टीम यहां 2 मैच खेलेगी। पहले फेज में 28 मार्च से 12 अप्रैल तक 20 मैच होने हैं। प्लेऑफ का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में ही खेला जाएगा।

84 नहीं, 74 मैच ही होंगे

टूर्नामेंट में 74 मैच ही खेले जाएंगे। लीग स्टेज में 70 मैच होंगे, वहीं प्लेऑफ स्टेज में 4 मैच खेले जाएंगे। पहले खबरें थीं कि इस सीजन 84 मैच होने हैं, लेकिन आईपीएल कमेटी ने मैचों की संख्या नहीं बढ़ाई।

आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 23 अप्रैल को पहली बार मुंबई में भिड़ेंगी। दोनों फिर 2 मई को चेन्नई में भी आमने-सामने होंगी। लीग स्टेज के आखिरी दिन 2 मैच होंगे। दोपहर में मुंबई का सामना राजस्थान से होगा, वहीं शाम को कोलकाता की टीम दिल्ली से भिड़ेगी।

हैदराबाद-दिल्ली दोपहर में 4-4 मैच खेलेंगे

10 टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस ही ऐसी 2 टीमें जिनका 1-1 मैच ही दोपहर में होगा। दोनों टीमें 13-13 मैच शाम को खेलेंगी। हैदराबाद और दिल्ली के सबसे ज्यादा 4-4 मैच दोपहर में 3.30 बजे शुरू होंगे। पंजाब और लखनऊ को 3-3 मैच दोपहर में खेलना है। वहीं राजस्थान, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के 2-2 मैच दोपहर में हैं। टोटल 12 दिन डबल हेडर खेले जाएंगे।

रायपुर और धर्मशाला 2 टीमों के सेकेंड होमग्राउंड

आईपीएल में 10 टीमें हैं। सभी अपने होमग्राउंड पर 7 और अपोजिशन टीम के होमग्राउंड पर 7 मैच खेलेंगी। 10 टीमों के 10 होमग्राउंड के अलावा राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने 2-2 होमग्राउंड चुने हैं। राजस्थान अपने शुरुआती 3 होम मैच गुवाहाटी में खेलेगी, वहीं 4 मैच जयपुर में खेले जाएंगे। बेंगलुरु का दूसरा होमग्राउंड रायपुर और पंजाब का मुल्लांपुर है।बेंगलुरु, मुंब ई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर, मुल्लांपुर और गुवाहाटी टूर्नामेंट के 13 वेन्यू हैं। यहां लीग स्टेज के 70 मैच होंगे। प्लेऑफ के 4 मैच में मुल्लांपुर और बेंगलुरु में खेले जाएंगे, लेकिन इनकी तारीखें अनाउंस होना बाकी है। MI vs CSK मैच 23 अप्रैल को सेकेंड फेज की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से होगी, लेकिन टीम इस बार हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। वहीं पहले फेज में टीम बेंगलुरु के मैदान पर RCB से पहला मैच खेलेगी।

IPL 2026
पूरा शेड्यूल

तारीख	मुकाबला	समय	वेन्यू
28 मार्च	RCB vs SRH	7:30 PM	बेंगलुरु
29 मार्च	MI vs KKR	7:30 PM	मुंबई
30 मार्च	RR vs CSK	7:30 PM	गुवाहाटी
31 मार्च	PBKS vs GT	7:30 PM	न्यू चंडीगढ़
1 अप्रैल	LSG vs DC	7:30 PM	लखनऊ
2 अप्रैल	KKR vs SRH	7:30 PM	कोलकाता
3 अप्रैल	CSK vs PBKS	7:30 PM	चेन्नई
4 अप्रैल	DC vs MI	3:30 PM	दिल्ली
4 अप्रैल	GT vs RR	7:30 PM	अहमदाबाद
5 अप्रैल	SRH vs LSG	3:30 PM	हैदराबाद
5 अप्रैल	RCB vs CSK	7:30 PM	बेंगलुरु
6 अप्रैल	KKR vs PBKS	7:30 PM	कोलकाता
7 अप्रैल	RR vs MI	7:30 PM	गुवाहाटी
8 अप्रैल	DC vs GT	7:30 PM	दिल्ली
9 अप्रैल	KKR vs LSG	7:30 PM	कोलकाता
10 अप्रैल	RR vs RCB	7:30 PM	गुवाहाटी
11 अप्रैल	PBKS vs SRH	3:30 PM	न्यू चंडीगढ़
11 अप्रैल	CSK vs DC	7:30 PM	चेन्नई
12 अप्रैल	LSG vs GT	3:30 PM	लखनऊ
12 अप्रैल	MI vs RCB	7:30 PM	मुंबई
13 अप्रैल	SRH vs RR	7:30 PM	हैदराबाद
14 अप्रैल	CSK vs KKR	7:30 PM	चेन्नई
15 अप्रैल	RCB vs LSG	7:30 PM	बेंगलुरु
16 अप्रैल	MI vs PBKS	7:30 PM	मुंबई
17 अप्रैल	GT vs KKR	7:30 PM	अहमदाबाद
18 अप्रैल	RCB vs DC	3:30 PM	बेंगलुरु
18 अप्रैल	SRH vs CSK	7:30 PM	हैदराबाद
19 अप्रैल	KKR vs RR	3:30 PM	कोलकाता
19 अप्रैल	PBKS vs LSG	7:30 PM	न्यू चंडीगढ़
20 अप्रैल	GT vs MI	7:30 PM	अहमदाबाद

IPL 2026
पूरा शेड्यूल

तारीख	मुकाबला	समय	वेन्यू
21 अप्रैल	SRH vs DC	7:30 PM	हैदराबाद
22 अप्रैल	LSG vs RR	7:30 PM	लखनऊ
23 अप्रैल	MI vs CSK	7:30 PM	मुंबई
24 अप्रैल	RCB vs GT	7:30 PM	बेंगलुरु
25 अप्रैल	DC vs PBKS	3:30 PM	दिल्ली
25 अप्रैल	RR vs SRH	7:30 PM	जयपुर
26 अप्रैल	GT vs CSK	3:30 PM	अहमदाबाद
26 अप्रैल	LSG vs KKR	7:30 PM	लखनऊ
27 अप्रैल	DC vs RCB	7:30 PM	दिल्ली
28 अप्रैल	PBKS vs RR	7:30 PM	न्यू चंडीगढ़
29 अप्रैल	MI vs SRH	7:30 PM	मुंबई
30 अप्रैल	GT vs RCB	7:30 PM	अहमदाबाद
1 मई	RR vs DC	7:30 PM	जयपुर
2 मई	CSK vs MI	7:30 PM	चेन्नई
3 मई	SRH vs KKR	3:30 PM	हैदराबाद
3 मई	GT vs PBKS	7:30 PM	अहमदाबाद
4 मई	MI vs LSG	7:30 PM	मुंबई
5 मई	DC vs CSK	7:30 PM	दिल्ली
6 मई	SRH vs PBKS	7:30 PM	हैदराबाद
7 मई	LSG vs RCB	7:30 PM	लखनऊ
8 मई	DC vs KKR	7:30 PM	दिल्ली
9 मई	RR vs GT	7:30 PM	जयपुर
10 मई	CSK vs LSG	3:30 PM	चेन्नई
10 मई	RCB vs MI	7:30 PM	रायपुर

ब्रीफ न्यूज

सैफ अंडर-20 फुटबॉल प्रतियोगिता में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा

दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ -सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम आज माले में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप बी के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। भारतीय टीम शनिवार को अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश से खेलेगी।

आईपीएल के इस सत्र में डिविलियर्स और उथप्पा को पीछे छोड़ सकते हैं राहुल

नई दिल्ली । इस माह के अंत में शुरु हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल के पास एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल करने का अवसर रहेगा। राहुल इस सत्र में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और अपने ही हमवतन रॉबिन उथप्पा को पीछे छोड़ सकते हैं। राहुल अभी 145 मैचों में 660 बाउंड्री के साथ नौवें नंबर पर हैं। राहुल ने 452 चौके और 208 छक्के लगाये हैं। राहुल को डिविलियर्स का रिकार्ड तोड़ने के लिए पांच और उथप्पा को पीछे छोड़ने चार बाउंड्री चाहिये। विलियर्स ने 184 आईपीएल मैचों में 664 बाउंड्री लगायी हैं। इस दौरान उन्होंने 413 चौके और 251 छक्के लगाये और दिल्ली व आरसीबी की ओर से खेला। वहीं उथप्पा ने 205 मुकाबलों में से 663 में बाउंड्री लगाई। उन्होंने 481 चौके और 182 छकके लगाये। वह चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) समेत पांच फ्रेंचाइजी में शामिल रहे। लीग में सबसे अधिक 1062 का रिकार्ड विराट कोहली का है जबकि 942 बाउंड्री के साथ ही रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर है। 920 बाउंड्री के साथ शिखर धवन तीसरे जबकि 899 के साथ ही डेविड वार्नर पांचवे नंबर पर हैं।

इंदौर में होगा भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 11 अक्टूबर को सीरीज का तीसरा मैच

मुंबई। दौर इंदौर के होल्कर स्टेडियम को एक और मैच की मेजबानी मिली है। 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मैच खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को टीम इंडिया के 2026-27 के घरेलू इंटरनेशनल सीजन का शेड्यूल जारी किया।

आगामी घरेलू सीजन में रोमांचक और एक्शन से भरपूर मुकाबले देखने को मिलेंगे। चार मेहमान टीमें वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलने के लिए भारत आएंगी। इस सीजन में 17 शहरों में 22 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे।

वनडे के बाद टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी

सीजन की शुरुआत वेस्टइंडीज के भारत दौरे से होगी। इस दौरे की शुरुआत

27 सितंबर 2026 से होगी। इस दौरान भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज और उसके बाद पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

वनडे मैच तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। टी-20 मैच लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में होंगे।

होलकर स्टेडियम में अब तक 4 टी-20 मैच खेले गए

पहला मैच: 2017 में श्रीलंका को 88 रनों से हराया।

दूसरा मैच: 2020 में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया।

तीसरा मैच: दक्षिण अफ्रीका ने 49 रन से भारत को हराया।

चौथा मैच: भारत ने 6 विकेट से अफगानिस्तान को हराया।

वेस्टइंडीज का भारत दौरा
(सितंबर-अक्टूबर 2026)

मैच	तारीख	समय	वेन्यू
पहला वनडे	27 सितंबर 2026	दोपहर 2:00 बजे	तिरुवनंतपुरम
दूसरा वनडे	30 सितंबर 2026	दोपहर 2:00 बजे	गुवाहाटी
तीसरा वनडे	03 अक्टूबर 2026	दोपहर 2:00 बजे	न्यू चंडीगढ़
पहला टी-20	06 अक्टूबर 2026	शाम 7:00 बजे	लखनऊ
दूसरा टी-20	09 अक्टूबर 2026	शाम 7:00 बजे	रांची
तीसरा टी-20	11 अक्टूबर 2026	शाम 7:00 बजे	इंदौर
चौथा टी-20	14 अक्टूबर 2026	शाम 7:00 बजे	हैदराबाद
पांचवां टी-20	17 अक्टूबर 2026	शाम 7:00 बजे	बेंगलुरु

इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पहला मैच कब खेलेंगे पैट कमिंस खुद दिया जवाब

चोट पर भी दिया अपडेट

दिल्ली। आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद को टूर्नामेंट के पहले मुकबाले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से भिड़ना है। पैट कमिंस इंजरी की वजह से टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले नहीं खेलेंगे। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह दूसरे हाफ और प्लेऑफ के सभी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।

पैट कमिंस ने 'बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स' पॉडकास्ट के साथ बात करते हुए कहा कि वह अपनी पीठ की इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं अभी भी पीठ की चोट से उबर रहा हूं, लेकिन अब

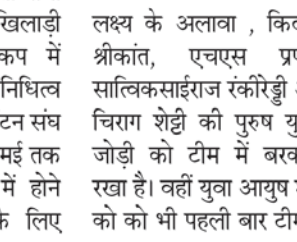

इंजरी पहले से बेहतर है। मैं नेट्स में गेंदबाजी कर रहा हूं। मैं अभी लगभग हर तीसरे दिन गेंदबाजी कर रहा हूं। प्लान के मुताबिक, टूर्नामेंट के बीच तक मेरे पूरी तरह से फिट होने की उम्मीद है। अगर कुछ गलत नहीं हुआ, तो मैं दूसरे हाफ और फाइनल खेलूंगा।'

कमिंस ने भरोसा जताया कि बतौर कप्तान ईशान किशन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि ईशान ने पिछले साल घरेलू टूर्नामेंट में शानदार कप्तानी की थी। ईशान ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में झारखंड को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया था। बल्ले से भी ईशान की हालिया फॉर्म शानदार चल रही है। टी20 विश्व कप 2026 में ईशान ने निरंतरता के साथ रन बनाए थे।

हालांकि, कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद का तेज गेंदबाजी अटैक काफी कमजोर दिख रहा है। ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और शिवम मावी के ऊपर टीम की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही हैदराबाद का स्पिन विभाग भी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। पिछले सीजन टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।

आईपीएल 2026 में इस बार उद्घाटन समारोह नहीं होगा : बीसीसीआई

भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी

बेंगलुरु। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19 सत्र में इस बार उद्घाटन समारोह नहीं रखा गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अनुसार उद्घाटन समारोह की जगह पर पिछली बार इस स्टेडियम में मची भगदड़ के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आईपीएल सत्र का पहला मुकाबला 28 मार्च को एम चेन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। पिछली बार हादसे में मारे गये लोगों के सम्मान में इस बार कोई पारंपरिक समारोह नहीं रखा गया है। इसी को लेकर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि है कि उद्घाटन मैच से पहले कोई

समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा पर 31 मई को खिताबी मुकाबले के दिन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सहयोग से समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछली बार आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में निकाली गई विक्ट्री परेड के दौरान भची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी। इसी दुखद हादसे को ध्यान में रखते हुए इस बार उद्घाटन समारोह को रद्द किया गया है जिससे मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा सके। इससे पहले भी आईपीएल उद्घाटन समारोह के बिना ही एक बार आईपीएल आयोजित किया गया था। साल 2019 में पुलवामा हादसे के बाद भी बीसीसीआई ने उद्घाटन कार्यक्रम को रद्द करते हुए उस पर खर्च होने वाली राशि शहीद जवानों के परिवारों को दान कर दी गई थी।

थॉमस और उबर कप बैडमिंटन में लक्ष्य और सिंधु पर रहेंगी नजरें

नई दिल्ली । भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन अगले महीने होने वाले थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष टीम की कमान संभालेंगे। वहीं ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उभरती खिलाड़ी उन्नति हुड्डा उबर कप में महिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय बैडमिंटन संघ ने 24 अप्रैल से तीन मई तक डेनमार्क के होर्सेंस में होने वाले थॉमस कप के लिए

लक्ष्य के अलावा , किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी को टीम में बरकरार रखा है। वहीं युवा आयुष शेट्टी को को भी पहली बार टीम में जगह दी है। पुरुष टीम में एमआर अर्जुन ध्रुव कपिला और किरण जॉर्ज को भी जगह मिली है।

वहीं उबर कप में सिंधु, शीर्ष युगल जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली भारती की ओर से पदक की प्रबल दावेदार रहेंगी। भारतीय टीम पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी पर इस बार उसका लक्ष्य और बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा।

मैनचेस्टर में महिला चैम्पियंस लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की हैना लुनाकविस्ट बेयर्न म्यूनिक के खिलाफ मैच में गोल दागती हुईं।

अंपायर ने गेंद को डेड बताया; टी-20 वर्ल्ड कप में से चर्चा में आए थे

उस्मान तारिक की नकल करना श्रीलंकाई गेंदबाज को भारी पड़ा

कोलंबो। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अनोखे बॉलिंग स्टाइल की नकल करना एक खिलाड़ी को भारी पड़ गया। श्रीलंका के रिचमंड कॉलेज में खेले गए एक मैच में गेंदबाज नेथुजा बशिथा ने तारिक की शैली अपनाने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने इसे नियमों के खिलाफ मानते हुए गेंद को डेड बॉल करार दिया। यह मैच गॉल में 21 मार्च को रिचमंड कॉलेज और महिंदा कॉलेज के बीच खेला गया था। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक इन दिनों अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली के कारण काफी चर्चा में हैं। हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय टी-20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। तारिक गेंद फेंकने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उनके खिलाफ खेलना मुश्किल हो जाता है। दरअसल, अंपायर का मानना था कि यह गेंदबाज के सामान्य बॉलिंग एक्शन का हिस्सा नहीं था, बल्कि बल्लेबाज का ध्यान भटकाने की एक कोशिश थी।

उस्मान तारिक का एक्शन क्यों है लीगल टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जब उस्मान तारिक ने अपनी गेंदबाजी से भारत और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों के बल्लेबाजों को परेशान किया था, तब उनके एक्शन पर भी सवाल उठे थे।

क्या कहता है क्रिकेट का नियम

क्रिकेट के नियमों के अनुसार, अगर कोई गेंदबाज जानबूझकर ऐसी हरकत करता है जिससे बल्लेबाज का ध्यान भटके या उसे परेशानी हो, तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल घोषित कर सकता है। गंभीर मामलों में अंपायर बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 पेनल्टी रन भी दे सकता है। बशिथा के मामले में अंपायर ने इसे अनुचित माना क्योंकि वे जानबूझकर तारिक की स्टाइल कॉपी कर रहे थे।

श्रीलंकाई बॉलर ने क्या किया

मैच के दौरान नेथुजा बशिथा ने उस्मान तारिक की तरह रुककर गेंदबाजी करने की कोशिश की। बशिथा अपने रन-अप के दौरान बीच में रुके और कई बार उछलकर गेंद फेंकी। अंपायर ने इसे तुरंत भांप लिया और गेंद को 'डेड बॉल' करार दे दिया।

केरपे में सामुदायिक पुलिसिंग, 400 ग्रामीण जुड़े, पुनर्वासित माओवादियों ने कहा—हिंसा छोड़ें, घर लौटें

स्वास्थ्य शिविर भी लगा

5 गांवों के 300-400 ग्रामीण शामिल

चलित थाना के जरिए जागरूकता

स्वास्थ्य शिविर में मुफ्त जांच व इलाज

बच्चों व युवाओं को सामग्री वितरण

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। थाना बेदरे क्षेत्र के ग्राम केरपे में शुक्रवार को सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केरपे सहित आसपास के 5 गांवों के करीब 300 से 400 ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के जरिए पुलिस ने ग्रामीणों को योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुटरू बृज किशोर यादव ने ग्रामीणों से कहा कि बदलते समय के साथ सभी को विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। जंगल में सक्रिय माओवादियों से उन्होंने परिवार के पास लौटकर सामान्य जीवन अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में पुनर्वासित माओवादियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जंगल और हिंसा का रास्ता केवल परेशानियों से भरा है। इससे न व्यक्ति का विकास होता है और न समाज का। उन्होंने अपने साथियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। इस दौरान चलित थाना और जनजागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। जरूरतमंदों को दैनिक उपयोग की सामग्री, बच्चों को पढ़ाई का सामान और युवाओं को खेल सामग्री वितरित की गई। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुटरू की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने शिक्षा और गांव के विकास में भागीदारी का संकल्प भी लिया।

पखांजूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: रामनवमी पर नाकाम की गौ-तस्करी की साजिश, 03 आरोपी गिरफ्तार

कांकेर/मूक पत्रिका

उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ-तस्करी के खिलाफएक बड़ी सफलता हासिल की है। रामनवमी के पावन पर्व पर जहाँ पूरा क्षेत्र भक्ति में डूबा था, वहीं कुछ असामाजिक तत्व तस्करी की फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के कड़े निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुर्रे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीन गौ-तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्रूरता की हदें पार, महाराष्ट्र के रास्ते तेलंगाना ले जाने की थी तैयारी पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक 'छोटा हाथी' वाहन (क्र. ख्रा 33 ञ्च 6556) में मवेशियों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी की और संदिग्ध वाहन को रोका। जाँच के दौरान पुलिस उस वक्त दंग रह गई जब वाहन के भीतर 03 गौवंश अत्यंत क्रूरतापूर्वक बंधे हुए पाए गए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इन मवेशियों को महाराष्ट्र के रास्ते तेलंगाना के बूचड़खाने ले जाने की योजना बना रहे थे।

महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तीनों आरोपी पकड़े गए आरोपियों की पहचान नरेश अरुण मराठे (29 वर्ष), सुशील लक्ष्मण पेंडाम (23 वर्ष) और विनोद शरद मेश्राम (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सभी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वाहन और मवेशियों

को जब्त कर लिया है। इन सभी के खिलाफ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम की मुस्तैदी की सराहना इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक लक्ष्मण केवट, एएसआई पुरुषोत्तम ठाकुर, प्रधान आरक्षक रविन्द्र ठाकुर और भुवन देहारी सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। कांकेर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दें, ताकि अपराधों पर लगाम कसी जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

कलेक्टर डॉ. कन्नौजे एवं पुलिस अधीक्षक वार्ष्णेय के सख्त निर्देश, जिले में कानून व्यवस्था, यातायात नियम और सड़क सुरक्षा का कड़ाई से पालन किया जाए

कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा व यातायात नियंत्रण को मजबूत करने कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एक्शन मोड में

सारंगढ़ में बिना अनुमति कार्यक्रम, आंदोलन एवं जुलूस निकालना प्रतिबंधित

सड़क चौड़ीकरण में सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने के निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा कानून समिति की बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में प्रशासन को और अधिक सक्रिय एवं सख्त रवैया अपनाने पर जोर दिया गया। इस बैठक में राजस्व, आरटीओ, पुलिस, नेशनल हाइवे, पशुधन, आबकारी, पंचायत, नगरीय निकाय के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की जुलूस, धरना, जयंती, उत्सव या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं एनडीपीएस एवं आबकारी एक्ट के तहत जब्त किए गए वाहनों की जल्द नीलामी करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने बताया कि फरवरी और मार्च माह में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इसे और कम करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने शराब और नशीले मादक द्रव्यों के सेवन कर वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) को सड़क अधोसंरचना में सुधार, रिफ्लेक्टर लगाने, सड़क किनारे रेलिंग पर रेडियम पट्टी लगाने एवं अंधे मोड़ों पर दिशा सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा, गढ़चौक क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अंतर्गत सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने के निर्देश दिए गए। सारंगढ़ शहर में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सारंगढ़ बस स्टैंड मे रात्रि में हलटिंग बसों को होटल के पीछे खड़े करने और नियमित जांच करने के लिए आरटीओ एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया। बिलाईगढ़ बस स्टैंड में बसों के प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए रूटीन चेकिंग करने तथा सभी बसों को निर्धारित नियमों के तहत बस स्टैंड होकर ही संचालन करने के निर्देश भी दिए गए।

कांकेर में संदिग्ध हालत में अज्ञात युवक का शव बरामद, पहचान के लिए पुलिस की अपील

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर :-जिला उत्तर बस्तर कांकेर 27 मार्च 2026 के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक की पहचान के लिए आमजन से सहयोग मांगा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम माकड़ी के पास बागुड़ पहाड़ी के नीचे खेत के समीप पत्थरों के पास एक युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ और फोटो दिखाकर पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। रंग सांवला, शरीर दुबला-पतला और बाल काले हैं। शरीर पर ऊपरी हिस्सा बिना कपड़ों के था, जबकि नीले रंग की जींस और एक टी-शर्ट (जिस पर "RU AMAZING IT HAPPEN" लिखा है) मिली है। शव को जिला अस्पताल कांकेर के मर्चुरी में सुरक्षित रखा गया है। कांकेर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को उक्त युवक के संबंध में कोई जानकारी हो, तो तत्काल थाना सिटी कोतवाली कांकेर के नंबर 94791-94109 या 94791-55125 पर संपर्क कर सूचना दें।

ईएसआई कार्ड में गड़बड़ी से कर्मचारियों में आक्रोश, यूनियन ने उठाई आवाज

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर- चारामा कांकेर यूनियन के शिकायत के बाद चारामा नगर पंचायत में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को आनन फानन में त्रुटिपूर्ण और असम्पूर्ण ई एसआइ कार्ड को वितरित किया गया है। उक्त आरोप आज छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारी यूनियन के राज्य अध्यक्ष द्वारका कोसरिया और महासचिव भाव सिंह कश्यप ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लगाया है। नेताओं ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी को और पहले ही यह ई एसआई कार्ड कर्मचारियों को वितरित करना था लेकिन ठेकेदार ने यूनियन द्वारा की गई शिकायत के बाद यह कार्ड कुछ कर्मचारियों को वितरित किया है अभी तक अनेकों कर्मचारी को यह कार्ड नहीं मिला है। नेताओं ने कहा है जिन कर्मचारियों को ई एसआई कार्ड वितरित किया गया है वो भी त्रुटिपूर्ण और असम्पूर्ण है। किसी कर्मचारी का स्थाई निवास और पता बिलासपुर जिला में दर्ज कर दिया गया। उनका ई एसआई के डिस्पेंसरी भी बिलासपुर दर्ज कर दिया गया है। चारामा के कोर्ड कर्मचारी अपने और अपने परिवार के इलाज के लिए क्या बिलासपुर जायेंगे? इस तरह किसी भी कर्मचारी के ई एसआई कार्ड में संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदायों और आश्रितों का नाम उल्लेख नहीं है। जबकि उक्त कार्ड में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों और आश्रितों का जानकारी उल्लेखित करना आवश्यक है। क्योंकि ई एसआई कार्ड से कर्मचारी के परिवार के सभी सदस्यों और आश्रितों का मुफ्त में ई एसआई के या निजी अस्पताल में चिकित्सा होता है। उनके नाम कार्ड में उल्लेखित नहीं होने के कारण परिवार के सदस्यों के इलाज की सुविधा से वंचित हो जायेंगे। यूनियन नेता ने नगर पंचायत चारामा के सीएमओ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सीएमओ की उदासीन, लापरवाही और ठेकेदार को संरक्षण दिए जाने के कारण ही कर्मचारी को उनके सुविधा से वंचित होना पड़ा है। कर्मचारियों का मुख्य नियोक्ता नगर पंचायत चाराना का सीएमओ है और इस लापरवाही का जिम्मेदार सीएमओ स्वयं है। यूनियन नेता ने सीएमओ से मांग किया है कि 7 दिवस के भीतर सभी प्लेसमेंट कर्मचारी के ई एसआई कार्ड के त्रुटियों को सुधार करने और कार्ड में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए उचित कार्यवाही करें।

यूनियन ने सीएमओ से यह भी मांग किया है कि प्लेसमेंट एजेंसी का अंतिम भुगतान को रोक दिया जाए ताकि कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके।

ताडोबा से सीखकर लौटे ग्रामीण, अब गांव में ही दिख रहे रोजगार के रास्ते, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के ईको डेवलपमेंट समिति सदस्यों का तीन दिन का अध्ययन दौरा

3 दिन का अध्ययन दौरा (19-21 मार्च)

मट्टीमरका और नम्बी गांव के ग्रामीण शामिल

होम-स्टे, सफारी और एडवेंचर एक्टिविटी की जानकारी

गांव में ही रोजगार बढ़ाने पर जोर

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार । जंगल के बीच रहने वाले ग्रामीण अब अपने ही इलाके में रोजगार के नए रास्ते खोजने लगे हैं। इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले गांवों के लोगों ने ताडोबा-अंधेरी टाइगर रिजर्व में ईको टूरिज्म के काम को करीब से समझा और अब उसी मॉडल को अपने यहां लागू करने की तैयारी में हैं। 19 से 21 मार्च तक चले इस तीन दिन के दौरे में मट्टीमरका और नम्बी गांव के लोग शामिल हुए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैसे छोटे-छोटे इंतजाम से भी गांव में अच्छी आमदनी की जा सकती है।ग्रामीणों ने होम-स्टे और टेंट में पर्यटकों को ठहराने का तरीका सीखा। साथ ही जंगल सफारी, नेचर ट्रेल और एडवेंचर गतिविधियों जैसे जिप लाइन, कायकिंग और कमांडो नेट जैसी चीजों को भी समझा। उन्हें बताया गया कि अगर गांव के लोग मिलकर काम करें तो बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा सकता है। इस दौरान यह भी समझाया गया कि साफ-सफाई, स्थानीय खाना और मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार ही ईको टूरिज्म की असली ताकत है। कई ग्रामीणों ने माना कि अब तक वे इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब उन्हें इसकी अहमियत समझ में आई है।दौरे के बाद ग्रामीणों में उत्साह नजर आया। उनका कहना है कि अगर सही मार्गदर्शन मिलता रहा तो आने वाले समय में गांव में ही रोजगार के मौके बन सकते हैं और बाहर जाने की जरूरत कम होगी।

बीजापुर में राम नवमी पर भव्य रैली, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर

भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रही चाक-चौबंद

बीजापुर/मूक पत्रिका

चैत्र नवरात्रि के अष्टमी की संध्या राम नवमी के उपलक्ष्य में व्यापारी संघ और मॉर्निंग क्लब बीजापुर के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को भव्य एवं आकर्षक रैली निकाली गई। रैली में शहरभर से बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए, जिससे पूरा नगर ÷जय श्रीराम÷ के नारों और भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा।रैली का शुभारंभ पुराने शिव मंदिर से हुआ, जो नए बस स्टैंड सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों से होते हुए नगर भ्रमण पर निकली। रैली के मार्ग में जगह-जगह नागरिकों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और पुष्प वर्षा कर आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया।रैली में शामिल युवाओं और श्रद्धालुओं ने डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर जमकर नृत्य किया। पारंपरिक परिधान, हाथों में भगवा ध्वज और उत्साह से भरे चेहरे इस आयोजन को विशेष आकर्षण बना रहे थे। पूरे आयोजन ने शहर में धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दिया। परीक्षा सत्र को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के निर्देशानुसार डीजे की ध्वनि सीमित रखी गई। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस के जवान पूरे मार्ग पर तैनात रहे, जिससे रैली शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। इस भव्य आयोजन के माध्यम से बीजापुर में राम नवमी का पर्व श्रद्धा, उल्लास और सामाजिक समरसता के साथ मनाया गया, जिसने नगरवासियों में एकता और भाईचारे की भावना को और प्रगाढ़ किया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।